● वर्ष-2
● अंक-199
रायपुर, बुधवार
12 अप्रैल 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmailĐcom

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

बिरनपुर के पास दो शव बरामद

कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच, एक सप्ताह में रिपोर्ट देने निर्देश

रायपुर/बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के हिंसा प्रभावित बिरनपुर गांव के पास पुलिस ने मंगलवार को पिता-पुत्र के शव बरामद किए। पुलिस ने यह जानकारी दी। बेमेतरा जिले के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ने बिरनपुर गांव से करीब पांच किलोमीटर दूर कोरवाय गांव से रहीम मोहम्मद (55) और उसके बेटे इदुक मोहम्मद (34) का शव बरामद किया है। दोनों बिरनपुर गांव के निवासी थे। एलेसेला ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, शवों के सिर पर चोट के निशान हैं। लेकिन मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा। उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनकी हत्या की गई या आपसी लड़ाई में उनकी मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

दिवंगत युवक के परि को सरकारी नौकरी और 10 लाख की सहायता राशि

बिरनपुर में दिवंगत 22 वर्षीय युवक के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी साथ ही 10 लाख रूपये की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों से मुलाक़ात के दौरान उक्त जानकारी दी। समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह साहू एवं अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाक़ात की थी। कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रशासकीय जाँच के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए है। एक सप्ताह में जाँच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील की है।

बेमेतरा शहर से 60 किलोमीटर दूर स्थित बिरनपुर गांव में आठ अप्रैल को स्कूली बच्चों के बीच लड़ाई के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। इस झड़प में एक स्थानीय निवासी भुनेश्वर साहू (23) की मौत हो गई थी और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। स्थानीय प्रशासन ने गांव में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगा दी है जिसके अनुसार चार या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। वहीं, गांव की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस ने अवरोधक लगा दिए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव और उसके आसपास करीब एक हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ हिंदू संगठनों ने सोमवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान राज्य के अधिकांश शहरों में दिन भर दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे।

अपराधी पकड़े गए इससे तेज़ और क्या कार्रवाई हो सकती है?-बघेल

बिरनपुर गांव में हिंसा के बाद फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। बड़ी संख्या में आसपास के गांव में जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बेमेतरा शहर से 60 किलोमीटर दूर स्थित बिरनपुर गांव में आठ अप्रैल को स्कूली बच्चों के बीच लड़ाई के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। इस झड़प में एक स्थानीय निवासी भुनेश्वर साहू की मौत हो गई थी और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बेमेतरा में हुई घटना पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा कुंठित हो चुकी है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे प्रदेश में लोग शांति से रहे रहे हैं लेकिन नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है वह दुर्भाग्यजनक है। घटना घटने के बाद अपराधी पकड़े गए इससे तेज़ और क्या कार्रवाई हो सकती है?बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिरनपुर हिंसा के दौरान मारे गए युवक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने युवक के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है।

सोशल मीडिया पर पुलिस ने कसा शिकंजा

बेमेतरा में बिगड़े माहौल के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। तीन मौतों के बाद अब सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों व विवादित पोस्ट कर हिंसा भड़काने वालो पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मैसेज भेजने वालों के साथ साथ ऐसे ग्रुपों के एडमिन पर भी कार्यवाही की जाएगी। बेमेतरा में हुई हिंसा व सांप्रदायिक तनाव के बीच अन्य जिलों की पुलिस भी एलर्ट मोड़ पर है। जीपीएम की पुलिस ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मैसेज व जिस ग्रुप में यह भेजा जा रहा है उसके एडमिन पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। जीपीएम जिले के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। जिसमे स्पष्ट चेतावनी जारी की गई है कि सभी सोशल साइट्स के एडमिनो को यह ध्यान रखना होगा कि उनके ग्रुप के कोई भी सदस्य ग्रुप में गलत खबर, विवादित पोस्ट, विवादित बातें, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने, दो पक्षों में विवाद बढ़ाने, या किसी जातियों के मध्य वैमन्यस्ता फैलाने संबंधी कोई भी मैसेज, पोस्ट, चित्रण या वीडियो फैलाता है या प्रसारित करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

इन दिनों

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के बाद पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने भले ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया हो, लेकिन इसेस उसके गढ़ महाराष्ट्र में चुनावी रूप से कोई फर्क पड़ने की संभावना नहीं है, जहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार सभी को स्वीकार्य हैं। एनसीपी का गठन 1999 में हुआ था। 2000 में इसने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया। ईसीआई ने 2014 और 2019 में अपने चुनावी प्रदर्शन के आधार पर एनसीपी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया और पार्टी को अब केवल महाराष्ट्र और नागालैंड में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करते हैं। हम चुनाव आयोग के आदेश का अध्ययन करेंगे और फिर विस्तार से जवाब देंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी की राजनीतिक गठजोड़ और सरकार बनाने या तोड़ने की क्षमता हमेशा से रही है। 82 वर्षीय शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने अभूतपूर्व राजनीतिक प्रयोग किए हैं। एनसीपी राज्य के नेताओं ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 100 सीटों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पार्टी समान विचारधारा वाली कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) को महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बैनर तले एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1999 के बाद से इसकी संख्या के चुनावों के बावजूद केंद्र और राज्य दोनों में पवार का प्रभाव कम नहीं हुआ है। नतीजतन, न तो सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) और न ही विपक्षी दल कांग्रेस और शिवसेना राकांपा को खारिज कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय स्वीकारिता के साथ दो मुख्यधारा के राजनीतिक दल हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनावों की बात आती है तो महाराष्ट्र में एनसीपी का चुनावी आधार अभी भी कायम है। 1999 में एनसीपी ने अपने गठन के बाद पहले विधानसभा चुनावों का सामना किया और 22.60 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 58 सीटें जीतीं। कांग्रेस 75 सीटों और 27.20 प्रतिशत वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। शिवसेना ने 69 सीटें (17.33 फीसदी वोट शेयर) और बीजेपी ने 56 सीटें (14.54 फीसदी वोट शेयर) जीतीं। पांच साल बाद एनसीपी ने 18.75 प्रतिशत के वोट शेयर के साथ 71 सीटों पर जीत हासिल करते हुए कांग्रेस पार्टी के रूप में पछाड़ दिया। प्रमुख पार्टी होने के बावजूद, पवार ने मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को सौंप दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार 1999 से 2014 तक चली। 2014 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और एनसीपी के लिए एक झटका था। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, भाजपा 288 में से 122 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद, राकांपा ने महाराष्ट्र में भाजपा को समर्थन देने का वादा किया। यह एक ओर एनसीपी के भीतर फूट से बचने की रणनीति थी।

नयी दिल्ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति जयदीप धनगर से मुलाकात की। कल वे प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी से मिल थे।

भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य रहेगी

नयी दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कहा कि देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। विभाग ने हालांकि कहा कि मॉनसून के दौरान अल नीनो की स्थिति बन सकती है, लेकिन सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) और उत्तरी गोलार्द्ध पर कम बर्फ पड़ने से इन स्थितियों का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। यह पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए राहत की खबर है। कृषि क्षेत्र फसलों की पैदावार के लिए मुख्य रूप से मॉनसून की बारिश पर ही निर्भर रहता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने बताया, भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून (जून से सितंबर) के दौरान सामान्य बारिश हो सकती है। यह दीर्घावधि औसत का 96 फीसदी (इसमें पांच प्रतिशत ऊपर या नीचे हो सकता) है। दीर्घावधि औसत 87 सेमी है। आईएमडी के महानिदेशक एम

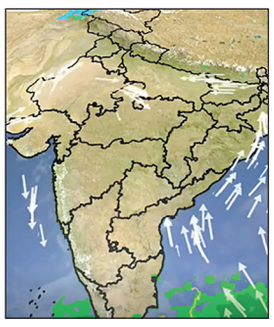

महापात्रा ने बताया कि बारिश के सामान्य और सामान्य से ज्यादा होने की 67 फीसदी संभावना है। उन्होंने बताया कि फरवरी मार्च 2023 के दौरान उत्तरी गोलार्द्ध और यूरेशिया में बर्फ से ढके क्षेत्र सामान्य से कम रहे हैं। उत्तरी गोलार्द्ध पर कम बर्फ का पड़ना समूचे भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश के लिए अनुकूल माना जाता है। महापात्रा ने कहा कि अगर अल नीनो की विकसित होती स्थितियों की वजह से किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ा, तो सकारात्मक आईओडी और उत्तरी गोलार्द्ध में कम बर्फ पड़ने का अनुकूल प्रभाव इन स्थितियों का मुकबला कर सकता है।

भारत में 2019 से लगातार चार वर्षों से मॉनसून के दौरान सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश हो रही है। महापात्रा ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत, पश्चिम मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान सामान्य और सामान्य से कम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। उन्होंने कहा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इससे सटे पूर्वी मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कई हिस्सों में तथा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश हो सकती है। आईएमडी के प्रमुख ने कहा कि अल नीनो की स्थितियां मॉनसून के दौरान विकसित हो सकती हैं और मॉनसून के दूसरे चरण में इसका असर महसूस हो सकता है।

प्रमुख समाचार

राहुल बोले- मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते

नई दिल्ली। लोकसभा से सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता के बाद पहली बार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरल में अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा किया। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। दोनों ने वायनाड में एक रोड-शो किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि वायनाड आना परिवार जैसा है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में डाल सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां कुछ का कब्जा हो, वहां कोई नहीं रहना चाहता। लोग आजाद देश में रहना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि एमपी सिर्फ एक टैग या पद है और बीजेपी मेरा टैग, पद और घर ले सकती है या मुझे जेल में डाल सकती है, लेकिन वे मुझे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोक सकती। उन्हें लगता है कि वे मेरे घर पुलिस भेजकर मुझे डरा देंगे...मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरा घर ले लिया।

भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए रहना चाहिए तैयार-जापानी विद्वान

नई दिल्ली। जापानी विद्वान ने चीन की विस्तारवादी नीति और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने की कोशिश के तहत 11 स्थानों का नाम बदलने की हालिया घोषणा के लिए उस पर निशाना साधा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत को चीन के क्षेत्रीय दावों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हडसन इंस्टीट्यूट में फेलो सटोरू नागाओ ने एएनआई को एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि उपमहाद्वीप में अपने पड़ोसियों के साथ बीजिंग का लगातार सीमा विवाद उसकी एक खतरनाक प्रवृत्ति है। चीन सोचता है कि ये उसका क्षेत्र है इसलिए उसके पास इसका नाम बदलने का अधिकार है और यही संदेश वो देना चाहता है। हम इस संदेश को समझते हैं कि चीन इन क्षेत्रों में अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। नागाओ ने कहा इसलिए यह खतरनाक है। जापानी विद्वान ने कहा कि चीन ने जापान के इलाके पर इसी तरह का दावा किया है और यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में सेनकाकू द्वीप, जैसा कि हम इसे कहते हैं, चीनी इसे अपने नाम से बुलाते हैं क्योंकि चीन यह संदेश देना चाहता है कि यह उनका क्षेत्र है और उन्हें इसका नाम बदलने का अधिकार है।

अरुणाचल प्रदेश हमारा था है और रहेगा-विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे को लेकर चीन ने आपत्ती जताई थी। चीन की आपत्तियों को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चीनी आधिकारिक

प्रवक्ता की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम चीनी आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा। हमेशा भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग बना रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की आपत्तियों को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि अमित शाह की अरुणाचल यात्रा पर चीन के आपत्ति जताने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की आपत्तियों का कोई कारण नहीं बनता और ये वास्तविकता को नहीं बदलेंगी। चीन ने सोमवार को अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे उस क्षेत्र पर चीनी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है।

तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज, आरएसएस के मार्च को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर

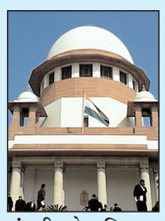

याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही संघ को तय मार्गों से मार्च निकालने की इजाजत दे दी थी। हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने इस मंजूरी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु में मार्च निकालने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

श्रीनगर में जी-20 की बैठक को लेकर बौखलाया पाकिस्तान, भारत पर लगाया आरोप

पाकिस्तान आज भी अपने नापाक हरकतों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान लगातार जम्मू-कश्मीर की तरक्की से जल रहा है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि श्रीनगर में जी-20 की एक बैठक होनी है। इसको लेकर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जता दी है। भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत जी20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होगी। इसी पर पाकिस्तान ने ''कड़ी आपत्ति'' जताई और इसे ''अपने हितों को पूरा करने वाला'' कदम बताया। भारत को पिछले साल दिसंबर में जी20 की अध्यक्षता मिली थी जो एक साल तक रहेगी। श्रीनगर में हो रही बैठक का विरोध करते हुए, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में इस आयोजन पर तीव्र रोष व्यक्त किया। मंत्रालय ने कहा कि 22-24 मई 2023 को श्रीनगर में जी-20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान कडी आपत्ति जताता है। इसके अलावा, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने लद्दाख के लेह और श्रीनगर में युवा मामलों पर एक सलाहकार मंच की दो अन्य बैठकों के कार्यक्रम का भी विरोध किया है। उसने साफ तौर पर कहा कि समान रूप से परेशान करने वाला है।

पायलट का धरना, वसुंधरा के नाम पर गहलोत के खिलाफ

अजय सेठिया

राजस्थान की सियासत का पारा चढ़ने लगा है। भाजपा में वसुंधरा राजे को लेकर पर्दे के पीछे से धूप-छाँव का खेल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में तलवारें म्यानों से बाहर आ गई हैं। पार्टी को 48 घंटे का नोटिस देकर सचिन पायलट धरने पर बैठ गए हैं। कुछ दिन पहले तक माना जा रहा था कि उन्होंने हालात से समझौता कर लिया है। फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा था। जो उन्होंने कुछ दिन पहले यह कह कर प्रकट किया था कि 25 सितंबर को जिन कांग्रेसी विधायकों ने आलाकमान की बुलाई बैठक के समानांतर बैठक बुलाई थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह गुस्सा अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं था, बल्कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ था। यह एक चेतावनी भी थी कि वह कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया।

अब अचानक सचिन ने तीन धारी तलवार चला दी, तलवार दोधारी ही होती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। उन्होंने एक ही तीर से कई निशाने साध लिए। उन्होंने यह कहते हुए एक दिन के धरने पर बैठने का एलान किया था कि साढ़े चार साल बीत गए, लेकिन अशोक गहलोत ने पिछली वसुंधरा सरकार के घोटालों की जांच नहीं करवाई। सचिन पायलट के इस फैसले से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सुखजिंदर सिंह रंधावा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। कांग्रेस ने सचिन के इस हमले से निपटने के दो तरीके अपनाए। दिल्ली में जयराम रमेश ने अशोक गहलोत की तारीफों के पुल बांधे और पंजाब में बैठे रंधावा ने सचिन पायलट के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट से उनकी बीस

मीटिंगे हुई , लेकिन उन्होने किसी भी मुलाक़ात में यह मुद्दा तो कभी उठाया ही नहीं था। कोई बात थी तो मिल बैठ कर हल निकालना चाहिए था, उन्होंने अशोक गहलोत की ओर से भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का हवाला भी दिया। कुल मिला कर उनकी लाईन भी गहलोत समर्थक थी। लेकिन पर्दे के पीछे सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की गई कि वह धरने पर न बैठें।

पायलट ने अनशन से एक दिन पहले ट्वीट करके धरना रद्द करने की कोशिशों पर पानी फेर दिया। पायलट ने ट्विट में लिखा - मन में खुशी, चेहरे पर मुस्कान, हर दिल में बसता यहां, राजस्थान का स्वाभिमान। इस तरह उन्होंने अपने धरने को राजस्थान के स्वाभिमान से जोड़ दिया, जबकि मामला उनके खुद के राजनीतिक स्वार्थ का है। क्योंकि वह बिना विधायकों के समर्थन के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। विधायकों का समर्थन न पहले उनके साथ था, न अब है। इसलिए अपने समर्थक विधायकों को उन्होंने धरने से दूर रहने को कहा है। क्योंकि अगर उनके समर्थक विधायक आए, तो फिर गिनती होगी और उनकी हवा निकल जाएगी। सिर्फ इतना ही नही, क्योंकि पार्टी ने उनके धरने को पार्टी विरोधी गतिविधि करार दे दिया है, इसलिए जिनकी सदस्यता 2020 में बच गई थी, वह अब चली जाएगी। सचिन पायलट के इस कदम से कुछ चीजें साफ़ दिखाई दे रही हैं, कुछ चीजों को डिकोड करना पड़ता है। राजनीति और कूटनीती में कही गई हर बात के कई अर्थ होते हैं। किसी नेता या डिप्लोमेट के हाव भाव और उसकी कही बात का जो हम मतलब निकाल रहे होते हैं, कई बार उसका वह मतलब होता ही नहीं, जो हम समझ रहे होते हैं, उससे कहीं गहरे मतलब होते हैं। इसलिए डिकोड करना पड़ता है कि क्या क्या नतीजे हो सकते हैं।

वैसे हर कोई हैरान है कि अचानक सचिन पायलट को क्या हुआ। धरना अशोक गहलोत के खिलाफ भी है, वसुंधरा के खिलाफ भी है। इसका पहला मतलब यह निकलता है कि वह कह रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं, वे एक दूसरे की रक्षा करते हैं। दूसरा मतलब यह निकलता है कि वह भाजपा में नहीं जाएंगे। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 2020 में जब उन्होंने बगावत की थी तो वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कुछ भाजपा नेताओं की डील को पलीता लगा दिया था। उस समय रणनीति यह बन रही थी कि सचिन पायलट अगर पर्याप्त विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ते है, तो भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। स्वाभाविक है इसका वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों ने विरोध किया था।

वसुंधरा राजे की भाजपा से अपनी नाराजगी है, वह यह कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया तीन साल तक पार्टी में उनके प्रभाव को खत्म करने का काम कर रहे थे। वैसे यह काम वह ऊपर के इशारे पर ही कर रहे थे। इन तीन सालों में वसुंधरा पार्टी की गतिविधियों से दूर रही। हालांकि अपने समर्थकों से मिलती रहीं। अब आलाकमान ने सतीश पूनिया को अध्यक्ष पद से हटा कर उनकी नाराजगी दूर कर दी है। पार्टी के पोस्टरों पर उनके फोटो चमक रहे हैं, और वह पार्टी के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगी है। तो संकेत यह जा रहा है कि भाजपा आलाकमान अंततः उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देगा।

चोरभट्टी और चेचानमेटा गांव में दो मकानों में लगाई आग

■ बीरनपुर में दो और लोगों की हत्या

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा के बीरनपुर गांव में भड़की हिंसा की आग ठंडी नहीं हो पा रही है। गांव में दो युवकों की और हत्या कर दी गई। दोनों के शव मंगलवार सुबह गांव से कुछ दूरी पर एक मकान में मिले हैं। पुलिस अफसरों ने इसकी पुष्टि की है। वहीं देर रात उपद्रवियों ने चोरभट्टी और चेचानमेटा गांव में भी दो मकानों में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। गांव में अभी भी फोर्स तैनात है। प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है।

देर रात दूसरे जिलों से मंगाई गई फोर्स

जानकारी के मुताबिक, देर शाम जब उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा गया, तभी हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गांव में बच्ची सहित चार लोगों के शव और मिले हैं। इनकी भी हत्या करने की बात कही गई है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल गांव में देर रात 600 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। दूसरे जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है। आने-जाने वालों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले परीक्षार्थियों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ भेजा जा रहा है।

शवों की शिनाख्तगी का प्रयास जारी

बेमेतरा एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला ने बताया कि बीरनपुर और साजा गांव के बीच कोरवा गांव है। वहां पर 45 से 50 साल उम्र के दो लोगों का शव मिला है। दोनों के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। ऐसे में आशंका है कि उनके सिर पर वारकर मारा गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आपसी लड़ाई में उनकी जान गई है या फिर हत्या की गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों शवों की शिनाख्तगी का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कई जगह से हिंसा की खबर आ रही है, लेकिन पुष्टि नहीं हो रही है।

युवक की हत्या के बाद भड़की हिंसा

दरअसल, 8 अप्रैल को बीरनपुर गांव में दो समुदायों के लड़कों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद इसमें बड़े भी शामिल हो गए। इस दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था। इसे देखते हुए जहां बीरनपुर में धारा-144 लगा दी गई थी, वहीं पूरे प्रदेश में भी पुलिस फोर्स सड़कों पर थी। संभावना थी कि इस बंद के बाद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हत्या के बाद फिर क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

बंद के दौरान भी हुआ था उपद्रव

छत्तीसगढ़ में सोमवार को बुलाए गए बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ था। बेमेतरा के बीरनपुर गांव में उपद्रवियों ने एक मकान फूंक दिया। इसके चलते वहां रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। इसमें आईजी आनंद छाबड़ा बाल-बाल बचे थे। वहीं रायपुर में भी उपद्रवियों ने रावणभाठा अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालन रोकने के लिए एक बस पर पथराव कर दिया था। साथ ही शहर के सभी बाजार और मॉल बंद करा दिए गए थे। इसके अलावा हाईवे जाम कर सड़क पर प्रदर्शन किया गया। देर शाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को गिरफ्तार किया गया था।

बेमेतरा जिले में धारा 144 लागू

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के विकासखंड साजा के ग्राम बिरनपुर में 08 अप्रैल 2023 को दो पक्षों में विवाद होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गया है, जिसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पदुम सिंह एल्मा द्वारा मंगलवार को एक आदेश जारी कर जिले में शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु संपूर्ण बेमेतरा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू किया गया है। जिले में लोक शांति बनाये रखने के लिये उपरोक्त क्षेत्र में जुलूस, धरना आमसभा व प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एक पक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जा रहा है। धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण बेमेतरा जिले में जूलूस धरना, आमसभा एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/ सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धार-धार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा और न ही एक साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति/संस्था गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड़ 19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और न ही बाधित करेगा।

बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 25 सौ प्रतिमाह, युवाओं में दिख रहा उत्साह

■ कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ रोजगार-स्वरोजगार स्थापित करने का मिलेगा अवसर

कोरबा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। पंजीयन कराने वाले बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद जिले के बेरोजगार युवाओं में बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए खासा उत्साह है। वे आवेदन करने में अपना रूचि दिखा रहे हैं। योजना के प्रारंभ होने के 10 दिवस के भीतर एक हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं ने पोर्टल में अपना पंजीयन कराया है। पंजीयन के साथ ही बेरोजगारों को सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उनके बैंक खातों का भी सत्यापन किया जा रहा है।

कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशन में जिले में बेरोजगारी भत्ता के लिए पंजीयन कराने वाले पात्र बेरोजगारों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य चल रहा है। इसके लिए कलस्टर बनाये गये हैं और पोर्टल में पंजीयन कराने के पश्चात सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। जिले में अभी तक एक हजार से अधिक आवेदन पंजीकृत हो चुके हैं। पंजीकृत आवेदनों का भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। बैंक खातों का सत्यापन के साथ ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। इधर बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगारों में इस पहल को लेकर बहुत उत्साह है। वे पात्रतानुसार अपना आवेदन कर रहे हैं।

ग्राम जोगीपाली के युवा दीपक पटेल ने बताया कि राज्य सरकार की अच्छी पहल है। इससे बहुत लाभ होगा। बेरोजगारी भत्ता के साथ कौशल प्रशिक्षण भी मिलेगा। इससे हमें आने वाले समय में नये अवसर मिलेंगे। ग्राम कनकी के युवक सूर्यकांत राजवाड़े ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद उन्होंने भी आवेदन किया है। उनका कहना है कि स्वीकृति के बाद कुछ जरूरी खर्च के लिए घर से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इच्छुक आवेदकों से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए पद में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्त्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।

संबलपुर के साप्ताहिक बाजार में दो दुकानों में लगी आग

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सोमवार देर रात दो दुकानों में आग लगने से 300 मुर्गे-मुर्गियां जलकर मर गए। वहां रखे 100 अंडे भी चपेट में आकर खराब हो गए हैं। दुकानों में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। सूचना मिलने पर दोनों दुकानदार मौके पर पहुंचे और किसी तरह से आग पर काबू पाया। हादसे के चलते करीब ढाई लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। मामला भानुप्रातपपुर थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, संबलपुर साप्ताहिक बाजार में स्थानीय निवासी शेख नजरीदीप और कमरूद्दीन खान की मुर्गा बेचने की दुकान है। रोज की तरह वह सोमवार शाम को भी दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात करीब 3 बजे उन्हें बाजार के आसपास रहने वालों ने सूचना दी कि दुकान में आग लग गई है। इस पर वे मौके पर पहुंचे और किसी तरह से पानी डालकर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी।

आग की चपेट में आकर दुकानों में रखे मुर्गे-मुर्गियां जलकर मर गए। दुकान संचालकों ने बताया कि आग लगने के कारण करीब दो लाख रुपये के मुर्गा-मुर्गी और अंडा समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया है। हादसे में कमरुद्दीन खान का करीब 40 हजार रुपये का का नुकसान होना बताया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आग लगने की घटना को लेकर जांच की जा रही है।

जयस्तंभ चौक में कांग्रेसियों ने फूंका पूर्व मंत्री चंद्राकर का पुतला

कांग्रेस की न्याय योजना को कहा था धान तस्करी योजना

राजनांदगांव। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पिछले दिनों कांग्रेस सरकार की धान खरीदी योजना को धान तस्करी न्याय योजना कहने पर कांग्रेसियों ने मंगलवार को जयस्तंभ चौक में उनका पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि चंद्राकर सदैव एक विवादित शख्स रहे हैं, प्रवक्ता के तौर पर उनके बयान की कड़ी निंदा करते कांग्रेस ने कहा कि माफी नहीं मांगने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

पिछले दिनों अजय चंद्राकर ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते कहा था कि किसान न्याय योजना धान तस्करी न्याय योजना बन गई है। उनके बयान को लेकर पूरे प्रदेश भर के कांग्रेसियों के नाराजगी व्याप्त है। मंगलवार को स्थानीय जयस्तंभ चौक में कांग्रेस नेताओं ने उनका पुतला फूंकने के बाद कड़ी भर्त्सना करते कहा कि भाजपा मुद्दाविहीन हो गई है, ऐसे में विवादों को बढ़ावा देने का काम पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं।

इस संबंध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने कहा कि राज्य में भाजपा हासिये पर चली गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 20 क्विंटल धान खरीदी किए जाने की घोषणा से भाजपा बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों को लेकर राज्य सरकार की योजनाएं बेहतर नतीजों के साथ आगे बढ़ रही है। श्री छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश में डॉ. रमन और अन्य नेता जनता के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उपलब्धियों को लेकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। श्री छाबड़ा ने कहा कि किसानों को लेकर दिए गए बयान से यह साफ हो गया कि चंद्राकर ने अपनी और भाजपा की किसान विरोधी सोच को दर्शाती है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम कोठारी ने कहा कि किसान न्याय योजना को लेकर चंद्राकर ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा किसानों को दिए जा रहे लाभ से विचलित है। उन्होंने कहा कि भाजपा योजना को फरेब के रूप में जाहिर कर रही है। जबकि 2013 के भाजपा शासन में 15 क्विंटल से 10 क्विंटल लिमिट तय कर दिया गया था। उन्होंने मांग करते कहा कि चंद्राकर ने यदि बयान को लेकर क्षमा नहीं मांगी तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। पुतला फूंकने के दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख, क्रांति बंजारे, अमित चंद्रवंशी, मदन साहू, सूर्यकांत जैन समेत अन्य कांग्रेसी शामिल थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़

सुकमा। ज़िले के पालामड़गु इलाक़े में व्यापारियों से नक्सलियों द्वारा मारपीट एवं लूटपाट की घटना के बाद उस इलाक़े में डीआरजी सीआरपीएफ़ 223 वी बटालियन एवं ज़िला बल की संयुक्त टीमें उस इलाक़े में भेजी गई थी। जहां तड़के सुबह चार बजे नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हूई उस इलाक़े में सर्चिंग में जवानों ने एक बाइक एवं नक्सलियों के वॉकीटॉकी सेट बरामद किए हैं। मुठभेड़ में पुलिस ने चार से पाँच नक्सलियों को गोली लगने का दावा किया है। वहीं मौक़े से भारी मात्रा अन्य सामग्रियाँ भी बरामद की गई है। गौरतलब है की नक्सलियों ने तीन व्यापारियों की बेदम पिटाई की थी जिसमें एक व्यापारी की मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस का बल उस इलाक़े में रवाना किया गया था।

हाथियों के दलों ने गांवों में घुसकर मचाया उत्पात

रामानुजगंज। रामानुजगंज के फॉरेस्ट रेंज में बीती रात हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने खेत में लगी फसलों को तबाह कर दिया। हाथियों का दल 4-5 दिनों से रामानुजगंज फोरेस्ट रेंज के चिनिया, महावीरगंज और कनकपुर के आसपास के जंगलों में भ्रमण कर रहा है। ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल निर्मित हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार दिन में हाथी जंगल में रहते हैं लेकिन रात होते ही भोजन की तलाश में गांव की तरफ आते हैं और तोडफ़ोड़ करते हैं। हाथियों के दल ने मक्का, गेहूं सहित अन्य फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया। खेतों में हाथियों के पैरों के निशान भी मौजूद है जिससे साफ पता चल रहा है कि हाथियों ने बीते रात अपनी भूख मिटाने के लिए खेत में धावा बोलकर फसलों को रौंदते हुए बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है।

पामगढ़ को नपं गठित किये जाने की अधिसूचना जारी

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 में वर्णित प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत पामगढ़ को नगर पंचायत गठित किये जाने के लिए विभाग की अधिसूचना माह अप्रैल 2023 द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। जिसके तहत ग्राम पंचायत पामगढ़ की सीमाएं ही नगर पंचायत पामगढ़ की सीमाएं होंगी। छत्तीसगढ़ नगर पालिका 1961 की धारा 6 में विहित प्रक्रिया के तहत अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय जांजगीर-चांपा, अधिसूचना द्वारा प्रभावित ग्राम पंचायत के कार्यालय तथा अधिसूचना द्वारा प्रभावित क्षेत्र में अन्य सहजदृश्य स्थानों में चस्पा कर प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपने आपत्ति, सुझाव कलेक्टर जांजगीर-चांपा को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस और समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

महुआ बीनने के लिए गई मां-बेटी को भालू ने दौड़ाया

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मंगलवार को महुआ बीनने के लिए गई मां और बेटी को भालू ने दौड़ा लिया। उससे बचने की कोशिश में भागते हुए मां पत्थर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि दोनों भालू से बचने में सफल हो गए। सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला बांगो थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम सिलहापहरी निवासी आसन सिंह बिंझवार की पत्नी कृष्णाबाई बिंझवार अपनी 6 साल की बेटी जमुना के साथ महुआ बीनने पास के जंगल में गई थी। महुआ बीनते समय अचानक मादा भालू सामने आ गई। भालू को देखकर मां-बेटी दोनों डर गए और अपनी जान बचाकर भागे। इस दौरान कृष्णा एक पत्थर से जा टकराई जिससे उसके सिर व शरीर पर गहरी चोट आई है।

प्री-मैट्रिक छात्रावास में अध्ययनरत 14 छात्राएं पाई गई कोरोना पॉजिटिव

राजनांदगांव। सोमवार को जिला मुख्यालय मोहला क्षेत्र के प्री-मैट्रिक छात्रावास में अध्ययनरत 14 छात्राएं जांच के दौरान कोरोना संक्रमित मिली है। इससे पहले रविवार को भी हॉस्टल में निवासरत 7 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली थी। हॉस्टल में रहने वाली 7 अन्य छात्राओं में भी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उन्हें होम आईसोलेशन के लिए घर भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर छुईखदान में 11, राजनांदगांव में 3, डोंगरगांव में दो और खैरागढ़ में एक नया संक्रमित मिला है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में मोतीपुर में दो पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक केस पूनम कॉलोनी का भी है।

समुदाय विशेष के साथ कारोबार नहीं करने की शपथ

बस्तर में वीएचपी-भाजपा नेताओं ने कहा- नहीं होगा किसी तरह का लेन-देन

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दो समुदायों के बीच जहां विवाद का मामला गरमाया हुआ है, और हिंसा थम नहीं रही है। वहीं अब जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा नेताओं ने समुदाय विशेष के साथ कारोबार नहीं करने की शपथ दिलाई है। इस शपथ के अनुसार, अब ये नेता ईसाई और मुस्लिमों के साथ किसी तरह से व्यवसायिक लेन-देन नहीं करेंगे। साथ ही व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर धार्मिक चिन्ह लगाएंगे। नेताओं के शपथ लेने वाला यह वीडियो सोमवार देर शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

वायरल वीडियो में भाजपा के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडेय, बस्तर रियासत के महाराज कमल चंद्र भंजदेव सहित कई नेता दिखाई दे रहे हैं। इसमें सकल्प दिलाया जा रहा है कि पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वह मुस्लिम या ईसाई हो, किसी भी व्यापारिक लेन-देन नहीं करेंगे। चाहे वह दूध, फल, सब्जी, गत्ता, किराना या कोई सामान हो, उनसे क्रय नहीं करूंगा। मैं यह प्रण लेता हूं कि उनका आर्थिक बहिष्कार करूंगा। वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से स्थानीय लोगों में इस तरह के शपथ को लेकर काफी नाराजगी है।

लोगों का कहना है कि जगदलपुर शहर की तासीर कभी भी इस तरह की नहीं रही है। इसके अलावा इस तरह के कृत्य से मुस्लिम और ईसाई समाज के लोग में भी नाराजगी नजर आ रही है। फिलहाल चुनावी दौर में ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब जनता क्या चुनती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

दीपका खदान में आठ घंटे से ज्यादा काम, चालकों ने रखा काम बंद

कोरबा। दीपका खदान में कोयला उठाव में लगी निजी कंपनी के ट्रक चालकों ने समयावधि को लेकर काम बंद हड़ताल कर दिया। वाहन खड़ी कर आरोप लगाया कि आठ घंटे के लिए काम पर रखा गया है, पर 12 घंटे तक काम लिया जा रहा है। बाद में इंटक जिलाध्यक्ष श्यामू जायसवाल ने आंदोलन का समर्थन किया और चालकों के साथ ठेका कंपनी प्रबंधन से वार्ता की। प्रबंधन ने आठ घंटे काम, वेतन बढ़ोत्तरी व मेडिकल सुविधा देने पर सहमति जताई, तब काम शुरू हुआ।

एसईसीएल की दीपका खदान में निजी कंपनी द्वारा कोयला उठा कर साइडिंग तक ट्रक के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसके लिए ट्रक चालक रखे गए हैं। रविवार को अचानक ट्रक चालकों ने काम बंद कर वाहन खड़ा कर दिया। इससे कोयला उठाव प्रभावित हो गया।

चालकों ने आरोप लगाया कि काम तय समय से अधिक है, आठ घंटे कार्य करने के लिए रखा गया था, 12 घंटे से भी अधिक कार्य लिया जा रहा, समय पर न तो छुट्टी मिल पा रही है और न ही वेतन बढ़ाया जा रहा है। चालकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। चालकों ने इसकी सूचना इंटक के जिलाध्यक्ष श्यामू जायसवाल व अन्य साथियों को दी। तब जायसवाल अपनी टीम मौके पर पहुंचे और चालक व कंपनी से बातचीत की। चालकों की कई मांगों पर सहमति बनी, उसके बाद आंदोलन को समाप्त किया गया। ठेका कंपनी ने सभी चालकों की ड्यूटी आठ घंटे करने ,वेतन बढ़ोतरी मेडिकल सुविधा देने की बात को मान लिया। इस दौरान जिला महासचिव खगेश बरेठ, ब्लाक अध्यक्ष अभिषेक कंवर, संत चौहान, बिंदेस कुमार, अविनाश, घासीदास, राहुल जायसवाल, जय, डेविड शांतिलाल, नवीन, कमलए सुरेश कुमार, कृष्णाए विजय, प्रदीप नायक, ऋतिक थापा,राघवेंद्र समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी रोजगार मेले में 71 हजार युवाओं को सौपेंगे नियुक्ति पत्र

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान 'रोजगार मेला' के तहत बृहस्पतिवार को करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है। पीएमओ ने कहा कि देश भर से चयनित युवाओं को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल सह टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जेई/सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न पदों पर तैनात किया जाएगा।

किरेन रिजिजू ने सोनिया गांधी के लेख को लेकर कसा तंज

नईदिल्ली। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी पर एक अंग्रेजी अखबार में लिखे संपादकीय में भाजपा की आलोचना करने को लेकर पलटवार किया है। सोनिया गांधी के संपादकीय में भाजपा सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र के सभी तीन स्तंभों को व्यवस्थित रूप से समाप्त किए जाने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने कहा है भारतीय लोकतंत्र केवल 1975 में एक बार मरा था और उसके बाद, यह फिर कभी नहीं हुआ और न कभी होगा। किरेन रिजिजू ने सोनिया गांधी पर अपने हमले को तेज करते हुए कहा कि हम कानून के शासन में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र की भावना देश में जीवित है। निर्वाचित सरकार से सभी प्रश्न पूछें, लेकिन अपने देश से सवाल न करें। भाजपा नेता ने कहा कि सोनिया गांधी लोकतंत्र के बारे में व्याख्यान दे रही हैं? कांग्रेस न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रही है।

गोवा के पूर्व सीएम लुइसिन्हो फलेरियो ने छोड़ी टीएमसी

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलेरियो ने आज संसद के उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सूत्रों के हवाले से बताया कि सभापति जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।फलेरियो ने एक समाचार पत्र से कहा कि मैंने टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया है। मैं फिलहाल किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं। सूत्रों की मानें तो लंबे समय से गोवा में पार्टी के मामलों से दरकिनार किए जा रहे फलेरियो को टीएमसी नेतृत्व द्वारा राज्यसभा से इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा था। टीएमसी सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी फलेरियो से नाराज है, क्योंकि उन्होंने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई के खिलाफ फतोर्दा से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। फलेरियो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सितंबर 2021 में टीएमसी में शामिल हो गए थे।

आया कांग्रेस का कॉल और नीतीश दिल्ली के लिए निकले

पटना। बिहार में आज नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। लंबे इंतजार के बाद सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। उद्देश्य स्पष्ट है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के अलावा उनका अन्य विपक्षी नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। यानी वे विपक्षी एकता के मिशन पर जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश को फोन किया था। नीतीश कुमार लंबे समय से विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस की ओर से पहल करने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले, उन्होंने माले के राज्य सम्मेलन में मौजूद कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विपक्षी एकता की पहल करने का अपना संदेश देने का आग्रह किया। पूर्णिया में आयोजित महागठबंधन की रैली में नीतीश ने कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस से बात करने का आग्रह किया। किसी भी तरह की देरी से नुकसान ही होगा।

भाजपा विधायक ईश्वरप्पा नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

बेंगलुरु। कर्नाटक की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। शिवमोगा से भाजपा विधायक केएस ईश्वरप्पा ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का एलान किया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, भाजपा की कर्नाटक इकाई के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। इसमें 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के निर्णय के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि वह चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। कन्नड़ में लिखे अपने पत्र में पूर्व उपमुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि यह निर्णय उन्होंने खुद लिया है। दरअसल, ईश्वरप्पा अक्सर अपने बयानों और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण विवादों में रहे हैं। ईश्वरप्पा जून में 75 साल के हो जाएंगे।

नार्थ ईस्ट में बोले केंद्रीय गृहमंत्री, 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी बनेंगे पीएम

भाजपा संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी

गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा असम की 14 में से 12 सीटें जीतेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और कार्यालय भाजपा का सभी गतिविधियों का केंद्र होता है।

भाजपा नेता ने कहा कि अभी नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों के चुनाव हुए और तीनों राज्यों में भाजपा सरकार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है।अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया, अगर वह ऐसा ही करते रहे तो न केवल पूर्वोत्तर से बल्कि पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बावजूद कांग्रेस हालिया चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई।

शाह ने कहा कि असम के 70 प्रतिशत हिस्से से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) हटाया जा चुका है, अन्य राज्यों के साथ सीमा विवाद को सुलझाया जा रहा है।

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ वे (विपक्ष) जितना बुरा बोलेंगे, भाजपा उतना आगे बढ़ते जाएगी। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त कर दिया है और वह क्षेत्र में शांति और तेज विकास लायी है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने दो कार्यकाल में दिखा दिया है कि वह पूर्वोत्तर के लिए क्या कर सकती है जो पिछली सरकारों द्वारा दशकों तक नहीं किया जा सका।

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने लिया यू-टर्न

विपक्षी एकता के लिए नहीं करेंगे जेपीसी का विरोध

मुंबई। शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच का विरोध करने से यू-टर्न लेते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि वह विपक्षी एकता के लिए जेपीसी का विरोध नहीं करेंगे। पवार ने मराठी समाचार चैनल एबीपी माझा से कहा कि विपक्षी दलों के हमारे मित्र अगर जेपीसी जांच पर जोर देते हैं तो विपक्षी एकता के लिए हम इसका विरोध नहीं करेंगे। हम उनके विचार से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा रुख विपक्षी एकता को नुकसान नहीं पहुंचाता, हम इस पर (जेपीसी जांच) जोर नहीं देंगे।

राकांपा प्रमुख ने शुक्रवार को यह कहने के बाद विपक्षी दलों में खलबली मचा दी कि वह इस मुद्दे पर जेपीसी जांच के खिलाफ हैं और अडानी को निशाना बनाया जा रहा है। पवार ने यह कहते हुए अपना रुख नरम कर लिया कि भाजपा समिति में बहुमत का आनंद लेगी जबकि विपक्ष अल्पमत में होगा। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि जेपीसी की ताकत संसद में राजनीतिक दलों की ताकत पर आधारित होगी। भाजपा के 200 से अधिक सांसद हैं और 21 सदस्यीय जेपीसी में अधिकतम सदस्य होंगे। विपक्ष में 5-6 सदस्य होंगे। क्या इतनी छोटी संख्या प्रभावी भूमिका निभा पाएगी? लेकिन फिर भी, यदि विपक्षी दल जेपीसी जांच पर जोर देते हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इससे पहले शरद पवार ने कहा था कि गौतम अडानी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।

सचिन पायलट ने खत्म किया अपना अनशन

बोले- भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा

जयपुर। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज जयपुर में 1 दिन के अनशन पर बैठे थे। हालांकि उनके अनशन को लेकर कांग्रेस में ही जबरदस्त तरीके से विवाद जारी था। सचिन पायलट के अनशन को अपनी ही सरकार के खिलाफ पर माना जा रहा था। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि सचिन पायलट ने अपने 1 दिन के उपवास को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहने वाला है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जब हम विपक्ष में थे तो हमने बहुत सारे घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागार किया था।

पायलट ने कहा कि हमने जनता से वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो घोटाले हुए उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब जब हम सरकार में हैं, 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई इसलिए आज मैंने अनशन रखा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप नए नहीं हैं, ये पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में हैं। मैंने कार्रवाई के लिए दो बार लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोग यह न सोचें कि हम जो वादा करते हैं और जो हम करते हैं उसमें कोई अंतर है।

खबर यह आई कि कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज प्रदेश के अपने दौरे को रद्द कर दिया। इससे पहले उन्होंने पायलट के इस अनशन को पार्टी के खिलाफ भी माना था। इसी को लेकर पायलट ने कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा कुछ दिन पहले ही प्रभारी बने हैं। मैंने पूर्व के प्रभारियों से भी बात की थी लेकिन यह भ्रष्टाचार का मामला अभी तक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे विरोध में खड़ी है: केजरीवाल

- **आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बोले**

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। इससे अरविंद केजरीवाल काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इसके लिए मैं सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, हमारे वोटरों और आलोचकों को बधाई देता हूं। चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने के एक दिन बाद, अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की हालिया गिरफ्तारी के बारे में बोलते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सभी भारत विरोधी ताकतें वर्तमान में पार्टी और उसके नेता के खिलाफ खड़ी हैं।

केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने अपने गठन के महज 10 साल में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। पार्टी अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से उपजी है और 2012 में बनाई गई थी। केजरीवाल ने कहा कि आज खुशी के मौके पर मनीष जी और जैन साहब की याद आ रही है अगर वे होते तो हमारी खुशी में चार चांद लग जाते, वे संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें मिल कर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं।

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी? ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये ज़िम्मेदारी अच्छे से पूरी करें। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आज आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। मैं आप के सभी स्वयंसेवकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम किया। मैं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को सलाम करता हूं। हम भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राजनीतिक स्टार्टअप हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

एशिया कप के लिए पाकिस्तान के रुख में आई नरमी

नईदिल्ली। एशिया कप 2023 को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के रुख में थोड़ी नरमी भी आई है। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। ऐसे में एशिया कप को लेकर सवाल उठने लगे थे। हालांकि, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूख में नरमी देखी गई है। इसके लिए पाकिस्तान अब बीच का रास्ता निकाल रहा है। माना जा रहा है कि भारत के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड झुकने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रबंध समिति के अध्यक्ष नजम सेठी ने साफ तौर पर कहा है कि एशिया कप की मेजबानी को हम किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे।

नजम सेठी ने साफ तौर पर कहा कि टूर्नामेंट आयोजन की जिम्मेदारी किसी और को हम नहीं दे सकते। हम हाइब्रिड मॉडल के आधार पर एशिया कप को कराने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आती है तो यह बहुत अच्छा है। अगर नहीं आती है तो उसके मुकाबले न्यूट्रल रिवेन्यू पर कराए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी जानकारी और पूरा शेड्यूल एशियन क्रिकेट काउंसिल को दे दी गई है। पिछले महीने एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई थी। जानकारी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच कब से कम दो मुकाबले एशिया कप में देखे जा सकते हैं। इन्हीं दो मुकाबलों से आधे से अधिक का रेवेन्यू आएगा। न्यूट्रल वैल्यू होने की वजह से अतिरिक्त बजट की भी जरूरत होगी। अपने बयान में सेठी ने कहा कि हमने एसीसी की बैठक में हाइब्रिड मॉडल पेश किया। पाकिस्तान और भारत कम से कम दो बार एक-दूसरे से खेलेंगे। यह मैच आधे से अधिक राजस्व उत्पन्न करता है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

60 हजारी हुआ सेंसेक्स निफ्टी 17,700 के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के कारण मंगलवार के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 311 अंक मजबूत हुआ, वहीं निफ्टी 98 अंकों की बढ़त के साथ 17,700 के पार निकल गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 311.21 अंक यानी 0.52 फीसदी मजबूत होकर 60,157.72 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ऊंचे में 60,267.68 तक गया और नीचे में 59,919.88 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 98.25 अंक यानी 0.56 फीसदी चढ़ा। निफ्टी कारोबार के अंत में 17,722.30 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ऊंचे में 17,748.75 तक गया और नीचे में 17,655.15 तक आया। सेंसेक्स के शेयरों में 20 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। कोटक बैंक, टाटा स्टील, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फिनसर्व सेंसेक्स के टॉप 5 गेनर्स रहे।

आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर का मार्च में टोल संग्रह बढ़कर 370 करोड़ रुपये पर

नईदिल्ली। आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स का मार्च में टोल संग्रह राजस्व 20.64 फीसदी बढ़कर 369.9 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा है कि एक साल पहले की समान अवधि में उसका अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों समेत कुल टोल राजस्व 306.6 करोड़ रुपये रहा था। मासिक आधार पर फरवरी, 2023 की तुलना में आईआरबी का टोल संग्रह मार्च, 2023 में 5.38 फीसदी बढ़ा है। यह फरवरी में 351 करोड़ रुपये रहा था। राजमार्गों पर टोल बूथों का संचालन करने वाली यह कंपनी राजमार्गों के विकास से भी जुड़ी हुई है। आईआरबी निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल पर संचालन करती है।

सेबी ने एआईएफ से निवेशकों को 'डायरेक्ट प्लान' का विकल्प देने को कहा

नईदिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने खर्च में पारदर्शिता लाने और गलत तरीके से बिक्री पर लगाम लगाने के लिए वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) से निवेशकों को 'डायरेक्ट प्लान' का विकल्प देने को कहा है। इसके अलावा, सेबी ने कमीशन वितरण के लिए चरणबद्ध मॉडल शुरू करने को भी कहा है और एआईएफ के निवेश से किसी निवेशक को बाहर निकलने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। नियामक ने कुछ उद्योग व्यवहार के संबंध में निजी नियोजन ज्ञापन में असंगतता और पर्याप्त खुलासे की कमी के मद्देनजर ये दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेबी ने दो अलग-अलग परिपत्रों में कहा है कि नए नियमों का मकसद एआईएफ में निवेश के लिए निवेशकों को लचीलापन देना, खर्च में पारदर्शिता लाना और गलत बिक्री को रोकना है।

एप्पल मुबंई में पहला, दिल्ली में दूसरा स्टोर खोलेगी

नईदिल्ली। आईफोन विनिर्माता एप्पल ने मंगलवार को घोषणा की कि वह मुंबई में अधिकारिक तौर पर अपना पहला स्टोर 18 अप्रैल को और दिल्ली में दूसरा स्टोर 20 अप्रैल को खोलेगी। वर्तमान में, कंपनी भारत में अपने उत्पादों को विशेष एप्पल प्रीमियम पुर्नविक्रेता स्टोर (एपीआर) के अलावा रिलायंस डिजिटल, क्रोमा जैसे बड़े प्रारूप वाली खुदरा श्रृंखलाओं, बहु-ब्रांड खुदरा दुकानों और ई-वाणिज्य मंच के जरिये बेचती है। कंपनी ने कहा, एप्पल ने भारत में ग्राहकों के लिए दो नए खुदरा स्थल खोलने की आज घोषणा की। 18 अप्रैल को मुंबई में एप्पल बीकेसी और 20 अप्रैल को दिल्ली में एप्पल साकेत खोला जाएगा।

गेम चेंजर हो सकता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स

डॉ. अश्विनी महाजन

एक दशक से अधिक समय से ई-कॉमर्स में भारत और दुनिया में भारी वृद्धि हुई है। भारत में कुल खुदरा व्यापार का लगभग 6.5 प्रतिशत आज ई-कॉमर्स के माध्यम से होता है। ई-कॉमर्स ने जीवन को आसान बना दिया है, क्योंकि लोगों को घर बैठे एक बटन क्लिक कर वस्तुएं और सेवाएं मिल जाती हैं। रेल-बस टिकट हो या हवाई यात्रा, होटल बुकिंग हो या टैक्सी, ऑटो से आना-जाना, सब सुविधाजनक हो गया है। ई-कॉमर्स से विभिन्न प्रकार की घरेलू और व्यावसायिक सेवाओं तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है, जिससे पारंपरिक व्यवसायों को भारी नुकसान हो रहा है।

सवाल केवल कमीशन का नहीं है, ये कंपनियां डेटा पर अपने एकाधिकार के कारण विभिन्न विक्रेताओं के बीच भेदभाव करती हैं और अपने पसंदीदा विक्रेताओं को वरीयता देती हैं। ऐसे में अन्य विक्रेताओं को नुकसान होता है। हालांकि ये कंपनियां अपने ग्राहकों को सस्ता सामान और सेवाएं प्रदान करने का दावा करती हैं, लेकिन अपनी आर्थिक ताकत के चलते ये छोटे पारंपरिक दुकानदारों, ट्रैवल एजेंटों आदि को बाजार से बाहर करने के लिए उपभोक्ताओं को भारी छूट देती हैं। अपने स्वयं के पैसे से और ड्राइवरों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने भारी प्रोत्साहन भी दिया, पर व्यवसाय स्थापित करने के बाद उबर सरीखे एग्रीगेटर उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर करते हैं और ड्राइवरों की कमाई का लगभग एक-तिहाई ये एग्रीगेटर छीन लेते हैं।

ऐसे में छोटे वेंडरों और गरीब कामगारों के पास केवल दो विकल्प हैं- या तो अपना शोषण होने दें या व्यवसाय छोड़ दें। इतना ही नहीं, ई-कॉमर्स कंपनियों के कैश बर्निंग मॉडल की वजह से परंपरागत कारोबारी भी धंधे से बाहर हो रहे हैं। चाहे किराना दुकान हो या रेडीमेड परिधान की दुकान या इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान के शोरूम या पारंपरिक ट्रैवल एजेंट, इन कंपनियों के आने से खुदरा व्यापार में रोजगार का क्षरण हुआ है। कहा जा सकता है कि आज का ई-कॉमर्स समावेशी नहीं है। हम ई-कॉमर्स को बंद नहीं कर सकते हैं और ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं है, पर सवाल विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का है। क्या हम इन ई-कॉमर्स दिग्गजों के लालच पर रोक लगा सकते हैं? इन सवालों के जवाब भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) में मिल रहे हैं, जो एक पंजीकृत कंपनी है।

ओएनडीसी नेटवर्क ई-कॉमर्स को एक चैनल प्रदान कर रहा है। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक कड़ी प्रदान करने की कोशिश करता है, जो शोषणकारी नहीं है। इस प्रणाली में कंपनियां डेटा पर एकाधिकार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के माध्यम से विक्रेताओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकती हैं। इसमें उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के विक्रेता, सेवा प्रदाता आदि को आसानी से खोज सकेंगे और ई-कॉमर्स बाजार में एकाधिकार के बजाय प्रतिस्पर्धा के आधार पर व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

आम तौर पर ये कंपनियां एक प्लेटफॉर्म के जरिये काम करती हैं। विक्रेता या सेवा प्रदाता संबंधित प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराते हैं और उन्हें कई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होता है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को छूट और प्रोत्साहन का लालच देकर उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यवसाय स्थापित होने के बाद वे उपभोक्ता और विक्रेता का शोषण करते हैं। ओएनडीसी वास्तव में विभिन्न प्लेटफॉर्म और उपभोक्ताओं के बीच की एक कड़ी है, जो लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करता है। अभी तक सामान्य ई-कॉमर्स में विक्रेता और सेवा प्रदाता उन प्लेटफॉर्म पर निर्भर होते हैं। ओएनडीसी ई-कॉमर्स को प्लेटफार्म के एकाधिकार से मुक्त करता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ई-कॉमर्स कंपनियों ने भी ओएनडीसी के नेटवर्क में शामिल होने में रुचि दिखाई है और कुछ प्लेटफॉर्म और भुगतान कंपनियां भी ओएनडीसी के साथ पंजीकृत हो रही हैं।

आदिवासियों के जीवन में सरकार ने क्या बदला

डॉ. भारती प्रवीण पवार

आदिवासी समुदाय आधुनिक विकास के लाभों से लाभान्वित होने में अनूठी चुनौतियों का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों में उन तक पहुंचने के लिए उनकी विशिष्ट चुनौतियों को पूरा करने के लिए अनुकूलित विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रावधान कर रही है। कृषि से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा से लेकर कौशल विकास तक भारत सरकार का इरादा हमेशा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का रहा है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जनजातीय उत्पाद के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता, कमजोर जनजातीय समूहों के विकास की योजना के जरिए भारत सरकार आदिवासियों के उत्थान और उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनाने की दिशा में काम कर रही है। आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए सरकार ने प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप और राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजनाओं को मजबूत किया। उन जिलों की पहचान की गई, जहां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच कम है। दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (श्रस्क्रस्) का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है। देश की जनजातीय आबादी में सिकल सेल रोग के प्रसार को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सिकल सेल रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। वित्त वर्ष 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 फीसदी कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन कार्यक्रमों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत 27 राज्यों में कुल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स (ष्ठ) की पहचान नीति आयोग ने की है। मैंने कई एस्पिरेशनल जनजातीय जिलों का दौरा कर आदिवासियों के साथ बातचीत की है और उन बदलावों के बारे में जानती हूं जो समाज में इस सरकार की पहल के रूप में आने लगे हैं। इनका प्रभाव अब प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में शिशु मृत्यु दर 62.1 (2005-06) से घटकर 41.6 (2019-21) हो गई है। वहीं पांच वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 95.7 (2005-06) से घटकर 50.3 (2019-21) हो गई है। संस्थागत प्रसव 17.7 फीसदी (2005-06) से बढ़कर 82.3 फीसदी (2019-21) हो गया है, साथ में 12-23 महीने के बच्चों का टीकाकरण 31.3 फीसदी (2005-06) से बढ़कर 76.8 फीसदी (2019-21) हो गया है। बजट में 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान में स्थापित किए जाने वाले 157 नए नर्सिंग कॉलेजों के लिए समर्थन का भी वादा किया गया है। यह भी दोहराया जाना चाहिए कि यह बजट शासन के सभी क्षेत्रों में सरकार को हासिल मील के पत्थरों पर आधारित है, खासतौर से ऐसी योजनाएं जो आबादी के सबसे हाशिए पर और कमजोर वर्गों को लक्षित करती हैं। उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने में योगदान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय, पीएम उज्ज्वला योजना में 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते और सबसे महत्वपूर्ण हमारा कोविड टीकाकरण अभियान है, जिसमें 102 करोड़ आबादी (220 करोड़ टीकाकरण के साथ) शामिल है। सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को अगले एक साल के लिए मुफ्त अनाज की आपूर्ति करके पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत समर्थन जारी है।

अमित शाह ने चीन को संदेश दे दिया

नीरज कुमार दुबे

चीन को शायद पता नहीं है कि यह 1962 वाला भारत नहीं है। आज के भारत का सिद्धांत है कि कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, आज के भारत का सिद्धांत है कि कोई हमें आजमाने की कोशिश ना करे। अभी हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ नामों को बदलने की हिमाकत दिखाई तो आज आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश के गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के एकदम नजदीक पहुँचे और चीन को साफ-साफ कह दिया कि वह समय चला गया, जब भारतीय भूमि पर कोई भी अतिक्रमण कर सकता था। अमित शाह ने सीमा के एकदम नजदीक से ऊँचे स्वर में स्पष्ट कहा कि आज सुई की नोंक के बराबर जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। उम्मीद है कि अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश यात्रा का विरोध कर रहे चीन ने भारत के गृह मंत्री का भाषण सुन लिया होगा और उनकी कही गयी बात को गाँठ बांध लिया होगा। भारत के गृह मंत्री का भाषण देश की अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा के प्रति भारत सरकार के दृढ़ रुख का तो समर्थन करता ही है साथ ही देश की जनता को भी आश्वस्त करता है कि देश सही हाथों में है। देखा जाये तो पहले की सरकारों के दौरान सीमायी गांवों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। यही नहीं, सेना को भी यह अपने आप ही देखना होता था कि चुनौतियों से जूझते हुए वह कैसे तैनाती वाले इलाकों तक पहुँचेगी। लेकिन यह नरेंद्र मोदी का भारत है। यहां विमर्श बदल गया है। अब सीमा के गांव आखिरी नहीं भारत के पहले गांव हैं। अब सेना को सिर्फ हथियारों से सुसज्जित नहीं किया जाता बल्कि उनकी तैनाती वाले इलाकों में ढाँचागत सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं।

हम आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अरुणाचल में सड़क संपर्क के लिए विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपये सहित 4800 करोड़ रुपये के केंद्रीय योगदान के साथ 'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम' को मंजूरी दी है। अमित शाह ने भारत-चीन सीमा से लगे किबिथू गांव में 'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम' की शुरुआत के साथ ही 'स्वर्ण जयंती सीमा प्रकाश कार्यक्रम' के तहत निर्मित राज्य सरकार की नौ सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएंगी। सीमाई इलाकों में सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार कितनी प्रयासरत है इसका एक उदाहरण हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल दौरे के दौरान भी सामने आया था जब उन्होंने एलएसी के पास एक पुल का उद्घाटन कर भारत की रक्षा तैयारियों को बल प्रदान किया तथा अपने संबोधन के माध्यम से चीन को कड़ा संदेश भी दिया। सियोम नदी पर बनाया गया पुल रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूरदराज के क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने में सहायक होगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन द्वारा देश के सीमावर्ती इलाकों में निर्मित 28 मूल ढांचा परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की थीं।

हम आपको बता दें कि चीन से चल रहे तनाव के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत-चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की सात नयी बटालियन और एक क्षेत्रीय हेडक्वार्टर के गठन को भी मंजूरी प्रदान की थी। इन बटालियन के निरीक्षण के लिये एक अतिरिक्त क्षेत्रीय हेडक्वार्टर का गठन करने का फैसला भी मोदी सरकार ने किया है। इसके लिये 9400 पदों का सृजन किया जायेगा। सरकार ने बताया है कि यह कार्य वर्ष 2025-26 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसमें कार्यालय, आवासीय पारिसर के निर्माण आदि कार्यों पर 1808 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा। साथ ही वेतन, राशन आदि पर प्रति वर्ष लगभग 963 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।

क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ?

यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत उत्तरी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2,967 गांव की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। पहले चरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के 455 सहित 662 गांव की पहचान की गई है।

हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल अक्टूबर में उत्तराखंड में चीन सीमा के नजदीक आखिरी गांव माणा में जब गये थे तब उन्होंने कहा था कि सीमाओं पर बसे गांव को आखिरी गांव नहीं पहला गांव कहा जाना चाहिए। इन गांवों में बनने वाले उत्पादों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री पर्यटकों से भी आग्रह करते रहे हैं कि वह जब भी कहीं घूमने जायें तो स्थानीय स्तर पर बनने वाले उत्पादों को अवश्य खरीदें। प्रधानमंत्री सीमा पर बसे गांवों के लोगों को देश का प्रहरी भी बताते रहे हैं। पिछले साल उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में भी पार्टी के लोगों का आह्वान किया था कि वह सीमाओं पर बसे गांवों में समय गुजारें। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए पूरी तरह केंद्र सरकार के खर्चे पर आधारित ''वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम'' को मंजूरी प्रदान की जोकि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत नहीं करेगा बल्कि सीमाओं पर स्थित भारत के पहले गांवों और ग्रामवासियों की तकदीर भी बदल देगा।

हम आपको बता दें कि सरकार का यह कदम देश की उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। इससे इन सीमावर्ती गांवों में सुनिश्चित आजीविका मुहैया करायी जा सकेगी जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। सरकारी बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम से चार राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लाकों में आजीविका के अवसर और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। इससे उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। इस कार्यक्रम से यहां रहने वाले लोगों के लिये गुणवत्तापूर्ण अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा इससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाना है। ''वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम'' के तहत इन इलाकों में विकास केंद्र विकसित करने, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को प्रोत्साहन देकर पर्यटन क्षमता को मजबूत बनाने और समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एनजीओ के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद की अवधारणा पर स्थायी इको-एग्री बिजनेस के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। वाइब्रेंट विलेज कार्य योजना को ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जाएगा। साथ ही इसके तहत केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं की शत-प्रतिशत पूर्णता सुनिश्चित की जाएगी। इनके तहत सभी मौसमों के अनुकूल सड़क, पेयजल, 24 घंटे, सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर के विकास पर जोर दिया जायेगा। इसमें कहा गया है कि यह सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से अलग होगा।

बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के पास देश की सीमा पर विरोधियों की चुनौतियों को विफल करने की पूरी क्षमता है। भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है और हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। यह संस्कृति और संस्कार हमें भगवान राम और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से विरासत में मिला है। मगर इसके साथ ही भारतीय सेना में सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता है और वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

शाण्डिल्यापानषद् (भाग-02)

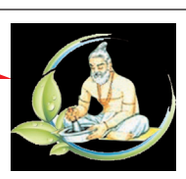

गतांक से आगे...

इसमें यम के दस भेद इस प्रकार हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, अल्प-आहार ग्रहण करना तथा पवित्रता। अहिंसा का तात्पर्य है मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा किसी भी प्राणी को कभी भी दु:ख न देना। सत्य का अर्थ है कि मन, वचन, शरीर एवं कर्म से जो हितकारी हो, वही वाणी प्राणियों के समक्ष बोलना। अस्तेय अर्थात् मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा दूसरों के धन-साधनों के प्रति निस्पृह रहना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि सभी अवस्थाओं में मन, वचन, शरीर एवं कर्म के द्वारा सभी तरह के मैथुन (असंयम) का परित्याग करना। दया अर्थात् समस्त प्राणियों पर सदैव अपना अनुग्रह बनाये रखना। आर्जव अर्थात् मन, वचन, शरीर एवं कर्म से लोगों के द्वारा उचित अथवा अनुचित व्यवहार करने अथवा न करने पर भी समभाव बनाये रखना। क्षमा का तात्पर्य है सदैव प्रिय-अप्रिय, पूजा अथवा ताड़ना आदि का बर्ताव किया जाए, तब भी उसे सहन करना। धृति अर्थात् धन हानि हो, अपने इष्ट मित्रों का वियोग अथवा संयोग हो, हर स्थिति में चित्त को स्थिर रखनां । अल्पाहार अर्थात् पेट में चौथा भाग खाली रहे, इस प्रकार अपने आहार में श्रेष्ठ घी, दुग्ध वाले मधुर पदार्थों का समावेश रखना। शौच का तात्पर्य है-बाह्य एवं अन्त: दोनों प्रकार की शुद्धि रखना। मिट्टी तथा जल के द्वारा बाहर की पवित्रता होती है तथा मन की शुद्धि आन्तरिक है जो अध्यात्म विद्या से होती है।

तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर-पूजन, सिद्धान्त-श्रवण, ही (लज्जा), मति, जप तथा व्रत- ये दस प्रकार के भेद नियम के कहे गये हैं। इसमें तप का तात्पर्य यह है कि विधिपूर्वक कृच्छ्र चान्द्रायण आदि से शरीर को सुखाना। संतोष अर्थात् दैव की इच्छा से जो भी कुछ प्राप्त हो जाए, उस पर संतोष रखना। आस्तिक्य का भाव यह है कि वेद द्वारा कहे हुए धर्म और अधर्म में विश्वास रखना। नीति पूर्वक प्राप्त हुए धन-धान्य आदि को श्रद्धापूर्वक गरीबों को देना ही दान कहा जाता है। ईश्वर-पूजन प्रसन्न स्वभाव से यथोचित मात्रा में विष्णु रुद्र आदि का पूजन-अर्चन करना। सिद्धान्त श्रवण अर्थात् वेदान्त के अर्थ का चिन्तन करना।

क्रमश:....

राणा सांगा ने मातृभूमि की रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए

12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में जन्मे महाराणा संग्रामसिंह ऊर्फ राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हुई थी। राणा कुम्भा के पोत्र और राणा रायमल के पुत्र राणा सांगा अपने पिता के बाद सन् 1509 में मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509 से 1527 तक रहा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, बाबर, महमूद खिलजी इस्लामिक शासकों के साथ युद्ध लड़ककर अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ बलिदान दे दिया था।

राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, महमूद खिलजी और बाबार के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी। उन्होंने सभी को धूल चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए थे फिर भी वे लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद वे लड़ने जाते थे। उनके घावों के कारण उन्हें मानवों का खंडहर भी कहा जाता था। खातोली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खातोली (कोटा) नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। कहते हैं कि इस युद्ध में सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खातोली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी जिसे भी पराजय का सामना करना पड़ा था। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर के साथ क्या समझौता किया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर चाहता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मेरा साथ दे, लेकिन राणा सांगा ने दिल्ली और आगरा के अभियान के दौरान बाबर का साथ नहीं दिया था और न ही उन्होंने बाबर को कोई न्योता दिया था। राणा को लगता था कि बाबर भी तैमूर की भांति दिल्ली में लूटपाट करके लौट जाएगा। किंतु 1526 ईस्वी में राणा सांगा ने देखा कि इब्राहीम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली में शासन करने लगा है तब राणा ने बाबर से युद्ध करने का निर्णय कर लिया। 1527 में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर जितनी सेना थी। बस फर्क यह था कि बाबार के पास गोला-बारूद का बड़ा जखीरा था और राणा के पास साहस एवं वीरता। युद्ध में बाबर ने राणा के साथ लड़ रहे लोदी सेनापति को लालच दिया जिसके चलते सांगा को धोखा देकर लोदी और उसकी सेना बाबर से जा मिली।

चुनावी चंदे पर गंभीरता से विचार करने की दरकार

वरुण गांधी

भारत के 2009 के आम चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा दो अरब डॉलर खर्च किए गए। यह आंकड़ा 2014 में पांच अरब और 2019 तक 8.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत का पिछला आम चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। यह अमेरिकी आंकड़े से भी आगे निकल गया, वहां 2015 में हुए चुनाव में 6.5 अरब डॉलर खर्च हुए थे। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार, भारत में इस खर्च का 10-12 फीसद मतदाताओं को सीधे नकद भुगतान के रूप में है। हमारे यहां चुनाव खर्च को लेकर राज्य वित्त पोषण का मामला पहले से विचारणीय रहा है। इस मुद्दे पर अब नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, 2021-22 में देश में राष्ट्रीय दलों की आय का 60 फीसद अज्ञात स्रोतों से आया और यह राशि 2,172 करोड़ रुपये से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2004-05 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों द्वारा 17,249 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोतों से जुटाए गए। इसमें कहीं दो राय नहीं कि चुनिंदा सुधारों के बावजूद दशकों से देश में चुनावी खर्च में पारदर्शिता की कमी रही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951), धारा 29(सी) के मुताबिक, राजनीतिक दलों के कोषाध्यक्षों को 20 हजार रुपये से अधिक के किसी भी योगदान के दस्तावेज चुनाव आयोग से साझा करना होता है।

1968 में इंदिरा गांधी की पहल पर राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट चंदे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अलबत्ता 1985 में इसे फिर से वैध ठहरा दिया गया। 1979 तक राजनीतिक दलों को आय और संपत्ति करों से भी छूट हासिल थी। हालांकि वे वार्षिक रिटर्न दाखिल करते थे और दस हजार रुपये से अधिक के दान और उसके दाताओं की पहचान का खुलासा करते थे। कहना नहीं होगा कि इस मामले में बाद में संशोधनों ने निगमों और राजनीतिक दलों की गोपनीयता को सामान्य नागरिकों के सूचना के अधिकार पर प्राथमिकता दी है। जाहिरा तौर पर इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की हमारी क्षमता प्रभावित हुई है। राजनीतिक दलों को अब आयकर विभाग और चुनाव आयोग को वार्षिक आय-व्यय ब्योरा देना तो जरूरी है, लेकिन वे अपने धन के स्रोतों का विस्तृत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

साफ है कि हमारे पास चुनावी खर्च और इसमें योगदान के खुलासे सीमित हैं। अमेरिका में चुनाव अभियान के खर्च के लिए दलों और उम्मीदवारों को वित्तीय मदद की परिभाषित सीमाएं हैं, जबकि चुनाव अभियान का खर्च ऐसी किसी सीमा से मुक्त है। साथ ही निगमों और श्रमिक संघों को उम्मीदवारों को सीधे वित्तीय मदद देने से मनाही है। इटली में राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट योगदान के लिए वार्षिक रिपोर्ट में इसके खुलासे के साथ बोर्ड की मंजूरी लेनी होती है। नीदरलैंड में लोगों और कंपनियों को सीमित दान और पार्टी सदस्यता राशि चुकाने में कर कटौती का प्रोत्साहनकारी प्रावधान है। हमें चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और दलों के लिए खर्च की स्पष्ट सीमा तय करने की जरूरत है। चुनाव अभियानों के संचालन की जटिलता का ध्यान रखते हुए इन सीमाओं को यथार्थवादी और प्रासंगिक होना चाहिए। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की रिपोर्ट के लिए जोर दे रहा है। डिजिटल लेन-देन की अनिवार्यता के साथ 2,000 रुपये से ऊपर के सभी दान का स्वागत किया जाना चाहिए। इस तरह के प्रावधानों के साथ छोटे दलों के लिए खेल का मैदान न्यायपूर्ण हो जाएगा और निर्दलीय उम्मीदवारों के पास सफलता का अधिक उचित अवसर होगा।

इस मामले में चुनावी बॉन्ड रामबाण साबित नहीं हुआ है। 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना को वित्त अधिनियम (2017) के जरिये पेश किया गया था और इसके जरिये लोगों, संस्थाओं या कंपनियों द्वारा ब्याज मुक्त चुनावी बॉन्ड की खरीद का रास्ता खोला गया था। इसमें न तो क्रेता और न ही राजनीतिक दल को ही यह बताने की जरूरत है कि दान किसे दिया गया है। इस बीच, भारत में चुनावों की विदेशी फंडिंग भी जारी है। यह विडंबना ही है कि एनजीओ चलाने वाले भारतीयों को विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि हमारे राजनीतिक दलों को कानूनन विदेशी चंदा प्राप्त करने की इजाजत है। आखिर में हम कह सकते हैं कि चुनाव के लिए सरकारी फंडिंग एक ऐसा विचार है, जिस पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। यह पश्चिम में पहले से व्यापक रूप से प्रचलित है। मसलन, फ्रांस में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सार्वजनिक सब्सिडी 1988 से शुरू की गई थी। इसके साथ ही वहां कॉरपोरेट दान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नीदरलैंड में 1970 के दशक से सार्वजनिक सब्सिडी दी जाती रही है। अलबत्ता वहां फंड वितरण पार्टी फाउंडेशन के माध्यम से होता है। इसी तरह, स्वीडन में राजनीतिक दलों के लिए सार्वजनिक सब्सिडी 1965 से मौजूद है।

भारत के संबंध में भी यह कोई नया विचार नहीं है। 1990 में चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की कि स्वतंत्र समर्थकों द्वारा चुनावी खर्च को दंडित करते हुए और राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट चंदे पर प्रतिबंध लगाते हुए चुनिंदा खर्चों के लिए राज्य वित्त पोषण करे। 1998 से आंशिक राज्य सब्सिडी दी भी गई है। राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क पर खाली समय का आवंटन एक ऐसी ही पहल है। 1998 में चुनावों के राज्य वित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्त समिति ने सिफारिश की कि चुनाव के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मुफ्त एअर टाइम साझा करने की अनिवार्यता को निजी चैनलों तक विस्तृत और इसके लिए जरूरी सब्सिडी मुहैया कराई जानी चाहिए।

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की निजी चंदे पर निर्भरता कम करने के लिए हमें चुनावों के लिए सरकारी फंडिंग की दिशा में बढ़ना चाहिए। साथ ही, पार्टी की सदस्यता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय चुनाव कोष में दान को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। चुनावी खर्च की मलिनता को दूर करने के लिए इस तरह की पहल की प्रासंगिकता बढ़ गई है। इससे वैसे उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतरने में बढ़ावा मिलेगा, जो स्वच्छ राजनीति और नीति-निर्माण पर बहस को आगे बढ़ाने में गंभीरता के साथ दिलचस्पी रखते हैं। 11 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय तय भी करने जा रहा है कि क्या चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाले दावों को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि भारत में हर विधायक अपने करिअर की शुरुआत झूठे रिटर्न फाइलिंग से करता है। लोकतंत्र और मतदान की शुचिता के लिए इस दिशा में ठोस और ईमानदार पहल समय की मांग है।

गांधी आज

राष्ट्रीय शिक्षा

हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था हिन्दुस्तान के 30 से 35 फीसदी लोगों को किस प्रकार का जीवन बिताना पड़ता है. इस विचार को सामने रखकर होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के 85 फीसदी लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती से गुजर करते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा की योजना उन्हें अच्छे किसान बना देने और खेती के आसपास चलनेवाले धंधों की जानकारी करा देने की दृष्टि से होनी चाहिए। शिक्षा से निर्वाह का प्रश्न हल होना चाहिए, अत: उद्योग-धंधों की शिक्षा शिक्षण का प्रधान अंग होना चाहिए। जनता के निर्वाह का मसला हल किए बिना संस्कार या ईश्वर का ज्ञान देनेवाली शिक्षा की बात करना बेकार है। ऐसी शिक्षा खेत में या देहात में ही दी जा सकती है-कस्बों या शहरों में यह शिक्षा नहीं मिल सकती।

इसके सिवा पढ़ना-लिखना आने के पहले शिक्षा प्राप्ति हो ही न सकती हो तो हिन्दुस्तान की जनता को शिक्षित बनाने में कई दशक लगेंगे पर अक्षर ज्ञान (पढ़ने लिखने के ज्ञान) का विरोध न करते हुए भी यह कहना जरूरी है कि शिक्षा उसके बिना भी दी जा सकती है और दी जानी चाहिए।

लिखने-पढ़ने का ज्ञान न होते हुए भी मनुष्य गिनना सीख सकता है अपने उद्योग धंधे संबंधी प्राथमिक विज्ञान प्राप्त कर सकता है, साहित्य समझ सकता है, सुन सकता है और कंठ कर सकता है, और शक्तिशाली ह तो रचना भी कर सकता है। इसके सिवा उसमें सत्य की लगन हो तो ईश्व का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है।

हमारे सैंकड़ों पढ़े-लिखों का ज्ञान-भंडार - अनेक पोथियों के पन्न उलटने के बाद भी-इतना अल्प होता है कि इतनी पूँजी प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों को लिखना पढ़ना सीखने की माथापच्ची में पड़ने की सलाह देने के बजाय यदि वे अपना ज्ञान उन्हें जबानी दें तो देखेंगे कि बहुत वर्ष की पढ़ाई वे थोड़े ही वक्त में जनता तक पहुँचा सकते हैं। 10. इसके सिवा भारतवर्ष की शिक्षा की पद्धति बिना खर्च की ही होनी चाहिए । 11. अत: थोड़े वर्षों में यह शिक्षा पूरी हो जाने का मोह हमें न होन चाहिए। उद्योग करते और आजीविका प्राप्त करते हुए यह शिक्षा जन्म भ चल सकती है।

यह शिक्षा पुस्तकों पर कम से कम अवलंबित होगी। इसका यह अर्थ नहीं कि पुस्तकें रहें ही नहीं, किन्तु वाचन की अपेक्षा वह श्रवण, दर्शन और क्रिया के द्वारा अधिक दी जानी चाहिए।

कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने ली हाईलेवल मीटिंग

■ टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश, सीएस की मैराथन बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना को लेकर आज अधिकारियों की हाईलेवल मीटिंग ली। इसमें प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी तैयारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सीएम के निर्देश पर कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर मुख्य सचिव बैठक लिए। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में सभी संभागों के आयुक्तों, सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और सीएमएचओ के साथ बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोपहर साढ़े तीन बजे बैठक हुई।

सभी जिलों में सैंपलों की जांच बढ़ाने के निर्देश जारी, ज्यादा से ज्यादा RTPCR जांच हो

मुख्यमंत्री केएस निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में अधिकारियों

की उच्च स्तरीय बैठक ली। कोविड-19 की स्थिति और इससे बचाव व रोकथाम की व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्य सचिव जैन ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जैन ने सभी जिलों को कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करने को कहा।

स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर.ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना के संभावित मरीजों के सैंपल जांच के निर्देश दिए गए हैं। सैंपलों की यथासंभव आरटीपीसीआर जांच करने को कहा गया है। पॉजिटिव पाए जाने वाले सैंपलों को व्होल जीनोम सिक्वेसिंग के लिए भेजा जा सके। जांच के लिए जरूरी किट और कन्ज्युमेबल्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आपात स्थिति की तैयारियों को परखने अधिकांश अस्पतालों में मॉकड्रिल पूर्ण किया जा चुका है। सभी कलेक्टरों को जनसामान्य के बीच कोविड अनुकूल व्यवहारों और आवश्यक सावधानियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निर्देशित किया गया है।

कलेक्टरों को कोविड प्रोटोकाल का गंभीरता से पालन करने और कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पतालों में कोविड के इलाजके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य जीवनरक्षक उपकरणों और दवाइयों की समुचित व्यवस्था रखें। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों में पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में संभागों के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल हुए। बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. और पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव मौजूद रहे।

24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 93 नए मरीज

24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 93 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 511 हो गयी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 24 कोरोना संक्रमित मरीज राजनांदगांव जिले से मिले हैं। रायगढ़ जिले में 14, दुर्ग और धमतरी में 11-11 एक्टिव मरीज मिले हैं।

इन जिलों में इतने कोरोना मरीज मिले

वहीं महासमुंद 10, बिलासपुर 8, कांकेर 7, सरगुजा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 6-6, बलरामपुर 3, बलौदाबाजार और कोरबा में 2-2 कोरोना मरीज मिले हैं। जांजगीर-चांपा और कोंडागांव में 1-1 मरीज मिले हैं। कोरोना से निपटने बीते दिनों जिला अस्पतालों में मॉकडिल किया गया।

दूसरी ओर भारत सरकार के आदेशानुसार कोविड रोकथाम और बचाव के लिए छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को लेटर जारी किया है।

संक्षिप्त समाचार

गृह मंत्री का ग्राम खम्हरिया में सम्मान

दुर्ग। दुर्ग ब्लाक के ग्राम खम्हरिया में ग्रामीण स्तरीय माँ कर्मा जयन्ती का आयोजन किया गया।जिसमें समाज की ओर से कार्यक्रम के मुख्यअतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का सम्मान श्रीफल व प्रतिक चिन्ह भेंट कर किया गया।इस अवसर पर प्रमुख रूप से खिलावन साहू, लोकनाथ साहू, दयाराम साहू, वामन साहू, द्वारिका साहू, सुमंत साहू सहित समाज की महिलाये व ग्रामीण जन उपस्थित थी।

राज्य सरकार किसानों को मुआवजा दे : देवाशीष बघेल

पाटन। सेवा सहकारी समिति कुर्मीगुंडरा के पूर्व संचालक मंडल सदस्य व किसान नेता देवाशीष बघेल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को अचानक हुई बरसात में फसलों के नुकसान का मुआवजा दे।श्री बघेल ने कहा कि किसानों ने अपने अपने खेतो में गेहूं चना सरसो सहित बाड़ियो में विभिन्न प्रकार की सब्जीया लगाई थी। लेकिन अचानक हुई बरसात से किसानों को भारी नुकसान हुआ है।जिसका परिक्षण पटवारी के माध्यम से कराकर सीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।ताकि पीड़ित किसानों को राहत मिल सके।साथ ही श्री बघेल ने छग के मुख्यमंत्री द्वारा किसानो के धान को अब समितियों के माध्यम से 20 क्विटल खरीदे जाने पर राज्य सरकार का आभार माना है। उन्होंने कहा कि अब छग के किसान आर्थिक रूप से और मजबूत होंगे?

63 लाख का गांजा जब्त घेराबंदी में पकड़े गए 2 तस्कर

सारंगढ़। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पुलिस ने 63 लाख रुपए की गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला बरमकेला थाना क्षेत्र का है। दरअसल, दोनों आरोपी ओड़िशा से गांजा लेकर आ रहे थे। इस दौरान मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने झनकपुर के पास घेराबंदी की और दोनों तस्करों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 315 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जो 63 लाख रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया है।

विकासखण्ड स्तरीय पशु मेला का आयोजन आज

कांकेर। पशुधन विकास विभाग कांकेर द्वारा विकासखण्ड स्तरीय पशु मेला का आयोजन 12 अप्रैल को प्रात: 09 बजे से ग्राम कापसी बाजार स्थल में किया जायेगा। पशु मेला में जिला पंचायत सदस्य एवं कृषि सभापति नरोत्तम पडोटी, ग्राम पंचायत कापसी के सरपंच चेतन नुरेटी, उप सरपंच श्रीमती राधाबाई जैन, जनपद सदस्य सावित्री सलाम, श्रीराम नेताम, ग्राम गायता रामधारी हिड़को, ग्राम पटेल रामाराम हिड़को, पूर्व सरपंच देवराज हिड़को और पूर्व उप सरपंच मेहतर पोया मौजूद रहेंगे।

समेंट कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, ठेका प्रथा खत्म करने की मांग

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसमें बड़ी संख्या में जिले के प्लेसमेंट कर्मचारी मौजूद रहे। यह धरना नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर किया जा रहा है। साथ ही उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि, सभी नगरीय निकायों से प्लेसमेंट या ठेका प्रथा को खत्म करना चाहिए। इसके साथ ही प्लेसमेंट कर्मचारियों का नगरीय निकायों में समायोजन किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान किया जाए। नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमित किया जाए। उन्हें 62 वर्ष तक नौकरी दी जाए। नगरीय निकायों में कार्यरत किसी भी प्लेसमेंट कर्मी को सेवा से अलग न किया जाए। कर्मचारियों ने सरकार से मांगें पूरी करने की मांग की है।

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : कलेक्टर

बिलासपुर। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने कहा कि जिले में चल रहे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के कार्यो में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। फिलहाल प्रगणक टीमों द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे सर्वेक्षण की प्रगति को कलेक्टर ने नाकाफी बताते हुए सर्वेक्षण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन भी सुचारू रूप से करने कहा। बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदनों के सत्यापन के लिए गठित भौतिक सत्यापन दल को प्रतिदिन आवेदनों को सत्यापन करने के निर्देश दिए। बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदक के पात्र होने पर बैंक से नाम और खाता संख्या सत्यापित होने के बाद उन्हें आदेश पत्र जारी करने और पोर्टल में दर्ज कराने को कहा। उन्होंने कहा कि दोनों कार्यो में किसी भी प्रकार की शिथिलिता न बरती जाएं। कलेक्टर ने आज यहां मंथन सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक टीएल की बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते हुए इस आशय के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं सहित विभागवार योजनाओं एवं टीएल प्रकरणों की गहन समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जयश्री जैन, नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत, एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

स्थानीय ग्रामीणों को हटाकर बाहरी मजदूरों से काम बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीण का आरोप

बालोद। भिलाई इस्पात संयंत्र दल्ली माइंस के गांव धोबेदंड में पेलेट प्लांट बन रहा है। जहां दूसरे राज्यों से मजदूरों को बुलाकर काम कराया जा रहा है। जबकि, स्थानीय मजदूरों को काम से निकाल दिया गया है। जिससे नाराज ग्रामीण अब भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि, यदि गांव में प्लांट खुल रहा है तो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। स्थानीय युवा बेरोजगारों, पढ़े लिखे लोगों को साथ ही रोजी मजदूरी करने वाले लोगों को काम मिलना चाहिए।

स्थानीय मजदूर कर रहे थे काम

ग्रामीणों ने बताया कि पहले प्लांट का अभी निर्माण कार्य चल रहा है। जिसमें सबसे पहले स्थानीय ग्रामीणों को रखा गया था कंपनी ने स्थानीय बेरोजगारों को काम देने की बात कही थी।लेकिन जब प्लांट का काम शुरु हुआ तो स्थानीय लोगों को हटाकर दूसरे राज्यों के मजदूरों को रख लिया गया। इसलिए, हम सब जिला प्रशासन और महाप्रबंधक भिलाई इस्पात संयंत्र से मांग कर रहे हैं कि, हमें वहां पर उचित रोजगार दिया जाए।

बाहरी मजदूरों को वापस भेजने की मांग

ग्रामीणों ने बताया कि, आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत यह गांव आता है। जल जंगल और जमीन हमारे कार्य क्षेत्र में हैं। इसलिए हमारे जमीन के अंतर्गत आने वाले आसपास पंचायत क्षेत्र के समस्त शिक्षित बेरोजगारों को यहां काम दिया जाए। बाहर से आए मजदूरों को तत्काल वापस भेजने की बात भी की जा रही है। यदि वापस स्थानीय लोगों को काम पर नहीं रखा जाता है। तो वह आगे रणनीति बनाएंगे और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।

ग्रामीणों के साथ धोखा

एक तरफ तो सरकार पलायन रोकने की बात करती है। दूसरी तरफ बीएसपी प्रबंधन स्थानीय लोगों को ही काम से निकाल रहा है। प्रोजेक्ट खोलने को लेकर ग्रामीण खुश थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि, ग्रामीणों को ठगा गया है।शत प्रतिशत स्थानीय लोगों को काम देने की बात कहकर, खोले जा रहे प्लांट से अब स्थानीय ही नदारद हैं।

बेमेतरा हिंसा पर अमरजीत बोले- ये छोटी सी घटना

सत्ता के नशे में बौराए खाद्य मंत्री : भाजपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा में एक व्यक्ति की मौत मामले में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक छोटी से घटना करार दिया है। इस पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने चौतरफा घेरते हुए निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन से घबराकर भूपेश बघेल की पुलिस रात के अंधेरे में एफआईआर दर्ज कर रही है। आप बहुत संख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करते रहिए हम आपकी कयराना हरकतों से घबराने वाले नहीं हैं। वहीं बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि मंत्री भगत अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे हुए हैं। कांग्रेस के मंत्री अमरजीत भगत इतना नीचे गिर गए हैं कि जिहादियों की ओर से एक हिंदू युवक की हत्या छोटी घटना लगती है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि जेहादियों की ओर से भुनेश्वर साहू की हत्या को छोटी घटना बताने दुखद है। इस वारदात से पूरा प्रदेश शोक में डूबा है पर मंत्री को छोटी सी घटना लग रही हैं क्योंकि ये तो दावत कर रहे हैं। इस बयान से कांग्रेस ने अपना हिंदू विरोधी चरित्र दिखा दिया है।

क्या कहा था खाद्य मंत्री ने

प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बेमेतरा हिंसा पर कहा था कि छोटी सी घटना पर बीजेपी छत्तीसगढ़ बंद करके बेवजह लोगों को परेशान कर रही है। जहां की घटना है, वहां बंद करना चाहिए और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। पूरे प्रदेश को बंद करवा कर लोगों सहित व्यवसायियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती, तो विरोध प्रदर्शन किया जाता तो उचिल लगता।

बीजेपी माहौल को दूषित कर रही : गृहमंत्री

मामले में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। अपराधी जो भी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो नाम दिए गए हैं उसमें से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति जो बचा हुआ है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश बंद को लेकर कहा कि बीजेपी माहौल को दूषित करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। हमारी सरकार बनने के बाद इस प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। घटना से वे दुखी हैं। जब कार्रवाई न होती तो कहा जा सकता था, लेकिन बंद करके लोगों को परेशान करना ये सही नहीं है। लोग सरकार पर विश्वास करें।

टीआई को रोड शो पड़ गया भारी, जॉइन करते ही सस्पेंड

बिलासपुर। फिल्मी स्टाइल में विदाई समारोह का रोड शो करने वाले टीआई को बिलासपुर आईजी ने सस्पेंड कर दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से बिलासपुर ट्रांसफर होने पर थानेदार सुरेंद्र स्वर्णकार को जबर्दस्त अंदाज में विदाई दी गई थी, जिसमें वे अपनी लग्जरी कार का सन रूफ खोलकर वर्दी में ब्लैक गॉगल लगाकर हाथ जोड़कर रोड शो भी शामिल हुए थे। टीआई की विदाई का यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और सुरेंद्र स्वर्णकार चर्चा में आ गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

दरअशळ तबादला होने के बाद थानेदार सुरेंद्र स्वर्णकार को उनके स्टाफ ने विदाई समारोह का आयोजन किया था। पुलिसकर्मियों ने उनकी विदाई समारोह को यादगार बनाने के लिए ढोल-ताशों के साथ ही उनकी कार को गुलाब की फूलों से सजाया था। जिस तरह से उनकी विदाई हुई, उस तरह का फेयरवेल बड़े-बड़े अधिकारियों को भी नहीं मिलता होगा।

ढोल-ताशों के साथ बारातियों की तरह विदाई लेकर फूलों से सजी अपनी लग्जरी कार से बिलासपुर पहुंचे। लेकिन, इससे पहले ही उनकी विदाई समारोह का यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ और निरीक्षक सुरेंद्र स्वर्णकार पूरे प्रदेश में चर्चा में आ गए। सोमवार को पुलिस लाइन में आमद देने के बाद वे एसपी संतोष सिंह और आईजी बद्रीनारायण मीणा से मिलने पहुंचे। उनके इस कार्यप्रणाली को पुलिस अफसरों ने भी अनुशासनहीनता माना है। यही वजह है कि बिलासपुर में जॉइन करते ही उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

एमसीबी में हाथियों ने घरों को बनाया निशाना

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) में खड़गवां के जंगलों में घूम रहे 2 हाथियों ने घरों को अपना निशाना बनाया है। हाथियों के आमद से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों के एक दल को वन परिक्षेत्र खड़गवां के बीट देवाडांड के बेलकामार गांव में घूमते देखा गया है। हालांकि अभी तक हाथियों ने किसी तरह की जनहानि नहीं की है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और हाथियों को किसी प्रकार भी छेड़खानी ना करने की हिदायत दी है। वन परिक्षेत्र खड़गवां में अक्सर हाथियों की आमद बनी रहती है। हाथियों के विचरण और ग्रामीणों के घरों को तोड़ने की खबरें इस क्षेत्र में आम हो गई हैं। यहां के घने जंगलों में हाथियों को अक्सर देखा जाता है। वन परिक्षेत्र खड़गवां में आमतौर पर कोरबा, कटघोरा से प्रवेश करने वाले हाथियों के दल को विचरण करते हुए देखा जा सकता है। वन परिक्षेत्र खड़गवां में हाथी अक्सर खाने की तलाश में जंगलों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण करते हुए पहुंच जाते हैं और महुआ खाने के लिए ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

नक्सलवाद के खिलाफ ड्रोन अटैक, बीजापुर और सुकमा में आसमान से बरसे बम

सुकमा। बस्तर में नक्सलियों के सफाए के लिए अब फोर्स ड्रोन अटैक की मदद ले रही है। बीजापुर और सुकमा के सुदूर नक्सल प्रभावित इलाके में बीते दिनों ड्रोन से हवाई हमले की पुष्टि हुई है। शुक्रवार को नक्सलियों के दक्षिण बस्तर सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी कर हवाई बमबारी का दावा किया।नक्सलियों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को इस हमले से जोड़कर देखा है। बीते महीने अमित शाह ने बस्तर दौरे में नक्सलियों के खात्मे की तैयारी अंतिम चरण में होने का दावा किया था। जिसके बाद से ही ड्रोन हमलों में इजाफा हुआ है।

ग्रामीणों की माने तो बीते सप्ताह शुक्रवार सुबह जब्बागट्टा, मीनागट्टा, कवरगट्टा, भट्टिगुड़ा गांव के मोरकोमेट्टा पहाड़ी में यह ड्रोन से हमला किया गया। ग्रामीणों के अनुसार सुबह करीब छह बजे पहली बमबारी हुई। फिर 5-5 मिनट के अंतराल में लगातार ड्रोन से बम दागे गए। इसके बाद हेलीकॉप्टर से गोलीबारी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 3 साल में 4 बार ड्रोन से हमला किया गया है।एक बार फिर ये हमले हुए हैं। इस तरह के हमले से सभी ग्रामीण आदिवासी डरे हुए हैं। यह ड्रोन हमला कब तक जारी

रहेगा इसका जिम्मेदार कौन है।इस बात का जवाब ग्रामीण मांग रहे हैं।

सुकमा और बीजापुर जिले की सरहद पर नक्सलियों के बाद ग्रामीणों ने भी हवाई हमले का आरोप लगाया है। साक्ष्य के तौर पर ग्रामीणों ने बमों के अवशेष को दिखाते हुए विरोध जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि ड्रोन से हमले के बाद हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग हुई। ग्रामीण खुद को बचाने अपने-अपने घरों की तरफ भागने लगे। इस दौरान कई ग्रामीण घायल हुए हैं। जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ग्रामीणों के मुताबिक उनका जीवनयापन खेती और वनोपज पर निर्भर है। इसके लिए उन्हें जंगल में जाना पड़ता है,लेकिन अब इस तरह के हमलों से उन्हें जान का खतरा है।

भरोसा सम्मेलन के लिए बस्तर में शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने डाला डेरा

प्रियंका गांधी आएंगी 13 को, सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी

जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय में आगामी 13 अप्रैल को शहर के लालबाग मैदान में कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन और प्रियंका गांधी के प्रवास की तैयारी को लेकर आला कांग्रेसी नेताओं का बस्तर आने का सिलसिला शुरू हो गया है, प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेडिया, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सप्तगिरी उल्का व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जगदलपुर में डेरा डाल चुके हैं। लालबाग मैदान में आयोजित भरोसे के सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। सम्मेलन के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल आगामी विस चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। कांग्रेस इस सम्मेलन में करीब एक लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा कर रही है।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के 13 अप्रैल को लालबाग मैदान में प्रस्तावित भरोसा सम्मेलन के लिए ऐसा डोम लगाया जा रहा है जिस पर पानी और आग का कोई असर नहीं होगा। वाटर और फायर प्रुफ डोम लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। यह पूरा कार्यक्रम महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए महिलाओं से जुड़े महिला एवं बाल विकास विभाग को महिलाओं को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय आजीविका मिशन को 40 से 50 महिलाओं को लाने का लक्ष्य दिया गया है। विभाग के लिए हर जिले का लक्ष्य तय कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों को भी हजारों में लक्ष्य दिया गया है। सभा तक महिलाओं को लाने और ले जाने का जिम्मा परिवहन विभाग को सौंपा गया है। विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी की हर दिन निगरानी की जा रही है।

सभा स्थल को भूपेश सरकार की उपलब्धियों से सजाने की तैयारी की जा रही है। सरकार की गोधन न्याय योजना से लेकर ऐसी सभी योजनाओं की बैनर-पोस्टर सभा स्थल पर लगाए जाएंगे जिनका प्रचार सरकार समय-समय पर करती रही है। इसके अलावा कांग्रेस संगठन से जुड़ी एक चित्र प्रदर्शनी की भी तैयारी की जा रही है, जिसमें नेहरू-गांधी परिवार के बस्तर प्रवास की अब तक की तस्वीरों को सजाया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु पहली बार जिस दिन बस्तर आए थे, उसी दिन प्रियंका गांधी भी बस्तर आ रही हैं। नेहरू पहली बार 13 अप्रैल 1955 को यहां आए थे। अब इसी तारीख को यानी 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी भी बस्तर आ रही हैं। सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने कांग्रेस जिला से लेकर ब्लॉक स्तर पर बैठक कर रही है और तैयारी में जुट गयी है।

महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर प्रियंका को घेरेगा महिला मोर्चा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को घेरेगा। आज महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय वर्चुअल बैठक आहुत की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप एवं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत सहित महिला मोर्चा की पदाधिकारी व कार्यकर्ता वर्चुअल माध्यम से शामिल हुई। बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बस्तर प्रवास पर बस्तर संभाग महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के नेतृत्व में घेरने की रणनीति बनाई गई। प्रदेश महिला मोर्चा भूपेश सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में एवं प्रियंका गांधी के वक्तव्य में हमेशा यह कहना कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस विषय पर सीधे संवाद-सीधे विरोध की मुहिम महिला मोर्चा द्वारा चलाई जाएगी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में प्रदेश की भूपेश सरकार से पूछेंगे कि कांग्रेस की सरकार साढ़े 4 सालों में शराबबंदी क्यों नहीं कर पाई? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक दुष्कर्म के अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पाये? पेंशन राशि क्यों नहीं बढ़ पाई? रेडी टू ईट बनाने वाली हजारों बहनों को क्यों बेरोजगार कर दिया।

तीन महीनों से विधवा बहनों को पेंशन नहीं

नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने लगाया आरोप

रायपुर। आज भाजपा पार्षद दल, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में महापौर एजाज ढ़ेबर से मिलकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रू देने की घोषणा के संबंध में चर्चा की। विदित हो कि, विगत 15 फरवरी को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यक्रम के अवसर पर मान.मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम रायपुर के लिए राशि 100 करोड़ रू की घोषणा की थी। आज भाजपा पार्षद दल ने इस 100 करोड़ का सच जानना चाहा और कहा कि आज पर्यन्त तक यह राशि नगर निगम के खाते में नही आयी है। भाजपा पार्षद दल ने पूरे 100 करोड़ रू से 70 वार्डो के पार्षदो के प्रस्तावों पर विकास कार्य करने की मांग की। चर्चा में महापौर ने बताया कि 100 करोड़ में से केवल 30 करोड के विकास कार्यो के प्रस्ताव 70 वार्डो से मंगाया जावेगा। जिसपर भाजपा पार्षदो ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि जब 100 करोड़ रू की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम रायपुर के लिए की है तो उस राशि से वार्डो के अंदर सड़क, बिजली, पानी, नाली, पुलिया जैसे मूलभूत कार्यो को करवाया जावें। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षो में पार्षदों के द्वारा बताये गए अधिकांश कार्य स्वीकृत नही हुए है। भाजपा पार्षदो ने कहा यदि महापौर को मुख्यमंत्री जी से वार्ड विकास के लिए राशि मांगने में संकोच हो रहा हो तो हम 100 करोड़ की राशि के लिए मुख्यमंत्री जी के पास जाने के लिए तैयार है।

साथ ही नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने यह आरोप लगाया कि विगत तीन महीनों से शासन की पेंशन योजनाओं की राशि हितग्राहियों को नही मिल पायी है, इसका जिम्मेदार कौन है ? गरीब हितग्राही पेंशन के लिए भटक रहें हैं, अगर एक सप्ताह के अंदर पेंशन की राशि हितग्राहियों को नही मिलेगी तो हितग्राहियों के साथ मिलकर नगर निगम में प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त ज्ञापन सौंपने के लिए उपनेताप्रतिपक्ष मनोज वर्मा, मृत्युजंय दुबे, डॉ.प्रमोद साहू, विनोद अग्रवाल, सीमा साहू, दीपक जायसवाल, रोहित साहू, रवि ध्रुव, सरिता वर्मा, विश्वदिनी पांडेय, कमलेश्वरी वर्मा, सुशीला धीवर, कामिनी देवांगन, सावित्री साहू, भोला साहू, सीमा मुकेश कंदोई, रजयंत ध्रुव, नारद कौशल मौजूद थे।

रसोइया संघ की अध्यक्ष रिहा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ रसोइया संघ चार दिवसीय हड़ताल पर है। आज हड़ताल का चौथा दिन है और अब रसोइया संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। पुलिस ने 24 घंटे बादं मध्यान्ह भोजन रसोईया सघ की अध्यक्ष नहीलू ओगरे को रिहा कर दिया है। उसे सोमवार को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान उसे महासमुंद की ओर ले जाने की जानकारी मिली है। वैसे बीती रात करीब 10 बजे नीलू को वापस छोड़ने के बाद पुनः पुलिस उठा ले गई थी। और आज दोपहर 1 बजे नीलू की बेटी ने मां को छोने की जानकारी दी है।

इससे ही आक्रोशित होकर रसोइया संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कह रहे हैं। रसोइया संघ की अध्यक्ष नीलू ओगरे का कहना है कि, छत्तीसगढ़ प्रदेश 33 जिलों के 146 विकास खंडों में संचालित 45 हज़ार 610 शालाओं में अध्ययनरत बच्चों के लिए 87026 रसोइया भोजन बनाते हैं। रसोइया और रसोइया सहायिका का मानदेय वर्तमान में 1500 प्रतिमाह है। जो सिर्फ 10 माह के लिए ही देय होता है, जिसके कारण अनेकों उन्हें अनेक समस्याओँ का सामना करना पड़ता है। बता दें कि, 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा केवल 300 रूपए की वृद्धि की गई, जिससे रसोइया संघ आक्रोशित है। इनकी मांग है कि, इनके मानदेय को कलेक्टर दर पर किया जाए। यदि ऐसा न हुआ तो आने वाले समय में संघ राजधानी रायपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा।

मध्यान्ह भोजन रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष के साथ की गई पुलिस प्रताडना शर्मनाक - बृजमोहन

रायपुर। पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अपने संगठन के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही मध्यान्ह भोजन रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे की वीडियो जारी होने के बाद उन पर पुलिस द्वारा थाने ले जाकर की गई प्रताडना व आपत्तिजनक व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मान कांग्रेस सरकार कितना करती है यहां पर दिख रहा है। नीलू ओगरे जो अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सशक्त महिला है। पुलिस ने यह हिमाकत इसलिए कि क्योंकि नीलू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी। मुख्यमंत्री बघेल ने सत्ता में आने के लिए हर किसी से वादा तो कर लिया पर अब वादा निभाने से मुकर रहे है। ऐसे में कोई अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत धरना प्रदर्शन कर अपने हक की बात आप तक पहुंचाएं तो आप डंडा चला देंगे? उनके बाल पकड़कर सड़क पर खींचेंगे, उनका कॉलर पकड़ेंगे? अपने अधिकारों की लड़ाई लडने वालों के साथ कांग्रेस सरकार का यह व्यवहार दुर्भावनापूर्ण और आपत्तिजनक है। और ऐसी हरकत डरी हुई सरकार करती है। बृजमोहन ने मुख्यमंत्री को चेतवानी भरे लहजे में कहा कि छत्तीसगढ़ की सेवा में जुटे कर्मचारियों के साथ छत्तीसगढ़ की आम जनता भी अब सड़क पर आकर आप से लड़ाई लड़ेगी।

बड़गांव - कुटेसर में निस्तार के लिए गंगरेल से पानी की मांग, सौंपा ज्ञापन

रायपुर । निस्तारी तालाबों को भरने गंगरेल से छोड़े जा रहे पानी को ग्राम बड़गांव व कुटेसर में निस्तारी पानी ?की समस्या को देखते हुये इन दोनों ग्रामों के तालाबों को भरने पहुंचवाने की मांग जल प्रबंध संभाग क्रमांक 1 के कार्यपालन अभियंता एम बोरकर को ज्ञापन सौंप दोनों ग्रामों के सरपंचों ने की है । गंगरेल बांध के मांढर शाखा नहर से निकले वितरक शाखा नहर क्रमांक 10 से इन ग्रामों को निस्तारी पानी पहुंचता है । मांढर शाखा नहर में निस्तारी हेतु पानी छोड़ा जा चुका है और यह पानी वितरक शाखा क्रमांक 10 में ?भी दौड़ना शुरू हो गया है वह मुख्य शाखा के अंतिम छोर के ग्राम पिपरहट्ठा - सिवनी तक पहुंच चुका है । 13 किलीमीटर लंबी इस शाखा से निकले माइनर के शुरुआती ग्राम सोनपैरी के बाद कुटेसर व बड़गांव - तोडगाव में पानी पहुंचता है । सोनपैरी का तालाब में पानी भरना शुरू हो गया है । बीते वर्ष के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुये इन दोनों ग्रामों के पंचायतों ने श्री बोरकर को ज्ञापन सौंप सोनपैरी के आगे निस्तारी पानी पहुंचवाने की सुनिश्चित व्यवस्था की मांग की? है । ग्राम पंचायत बड़गांव के सरपंच श्रीमती रामबती मुरारी यादव व कुटेसर के सरपंच श्रीमती कामिनी लक्ष्मण यादव ने यह ज्ञापन सौंपने के साथ - साथ रायपुर जिला जल उपभोक्ता संस्था संघ के अध्यक्ष रहे भूपेन्द्र शर्मा से भी बीते वर्षों की तरह इन ग्रामों तक पानी पहुंचवाने सहयोग का आग्रह किया है ।

मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने भाजपा करेंगी कार्यक्रम

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर के संगठन जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रखी गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन सिंह, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक तथा विधायक शिवरतन शर्मा ने उपस्थित रहकर आगामी चुनाव रणनीति के मद्देनजर जिला प्रभारियों व सह प्रभारियों का मार्गदर्शन किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी जिला प्रभारी व सह प्रभारी बूथ सशक्तिकरण के तहत प्रत्येक बूथ तक जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 11- 11 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी और 25 लोगों को सदस्य और पन्ना प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक बूथ में मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने के उपलक्ष्य में 100 की संख्या में जनता के साथ यह एपिसोड सुनने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसी तरह प्रत्येक बूथ में कम-से-कम 5 वॉल राइटिंग करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में तय किया गया कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत प्रमुख नेताओं का हर दिन प्रवास हर जिले के प्रमुख का एक-दूसरे के जिले में होगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक समरसता भोज का आयोजन कर भोजन करेंगे। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक तथा विधायक शिवरतन शर्मा ने दी।

छत्तीसगढ़ प्रवास पर प्रियंका गांधी से मिलना चाहते है, पेंशनर्स महासंघ के प्रतिनिधि मंडल

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद 22 वर्षो से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49 हटाकर दोनों राज्यो के बीच पेंशनरों के आर्थिक दायित्वों का बंटवारा करने और मध्यप्रदेश शासन भोपाल के 30 जनवरी23 के लम्बित प्रस्ताव पर पेंशनरो को छत्तीसगढ़ शासन से 5त्न प्रतिशत महंगाई राहत देने हेतु सहमति देने और केन्द्र के समान 42त्न महंगाई राहत की मांग को लेकर राज्य में भारतीय राज्य पेन्शनर्स महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को छत्तीसगढ़ प्रवास में 13 अप्रेल 23 को आने पर कांग्रेस पार्टी शीर्षस्थ नेता प्रियंका गांधी से मिलने हेतु बस्तर सम्भाग के अध्यक्ष राम नारायण ताटी ने जिला प्रशासन जगदलपुर को पत्र देकर प्रत्यक्ष भेंट हेतु समय निर्धारित करने की मांग की है।

जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेन्द्र नामदेव, प्रदेश अध्यक्ष जय प्रकाश मिश्रा ने आगे बताया है कि राज्य के पेंशनरों की मुख्य समस्या मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के बीच पेंशनरी दायित्व का बटवारा के धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार ज्ञापन देकर जोर रहे है।मगर भूपेश सरकार पेंशनर्स की समस्या को लेकर आँख बंद किये हुये है जिसके कारण राज्य के पेंशनरों में असंतोष व्याप्त है। इसके पहले के मुख्यमंत्री अजीत जोगी और डॉ रमनसिंह सरकार ने भी इन मुद्दों को हल नहीं किया।जिसका खामियाजा 22 वर्षो से दोनों ही राज्य के पेन्शनर भुगतने को मजबूर है। इसी तरह लंबित 42 त्न प्रतिशत महंगाई राहत के भुगतान पर इस सरकार की चुप्पी अब पेंशनरों को खलने लगी है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

बाल विवाह विरोधी एवं विधवा विवाह के समर्थक थे ज्योतिबा फूले-कौशिक

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने समाज सुधारक ज्योतिबा गोविंदराव फूले के जयंती समारोह के अवसर पर बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 276 ग्राम हरदीकला में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित किया एवं सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम के अन्तर्गत भाजपा कार्यकर्ता मंजू टण्डन के निवास में महिलाओं के साथ सहभोज किया। इस अवसर पर उन्होनें कहा कि ज्योतिबाराव गोविंदराव फूले 19वीं सदी के एक समाज सुधारक, समाज प्रबोध, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होनें अपना पूरा जीवन मातृशक्ति को शिक्षा का अधिकार दिलाने,बाल विवाह को बंद कराने में लगा दिया वे फूले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से सामाज को मुक्त करना चाहते थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। उन्होनें कहा कि ज्योतिबाराव फूले ने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थीं।

जेहादी उन्माद और उसके पैरोकारों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा हिन्दू समाज- साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने बिरनपुर हिंसा में जान गंवाने वाले युवक भुनेश्वर साहू की मृत्यु के चार दिन बाद सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति ने इस ऐलान के जरिये छत्तीसगढ़ की भावना का अपमान किया है। जेहादी उन्माद के बचाव में कांग्रेस सरकार ने एक हिन्दू युवा की जान की कीमत 10 लाख रुपये तय की है। समाज ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। भूपेश बघेल सरकार ने हिन्दू समाज सहित पूरे छत्तीसगढ़िया समाज के जख्मों पर नमक छिड़का है।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल ने गांधी परिवार की चाटुकारिता के लिए यूपी में 50 50 लाख बांटे और छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे के लिए पूरे प्रदेश के दबाव के बाद मात्र 10 लाख की घोषणा की। इससे ज्यादा रकम के तो प्रियंका गांधी की गाड़ी से रोंदने के लिए गुलाब के फूल बिछाए थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि जेहादी उन्माद में निर्दोष हिन्दू युवक की नृशंस हत्या हो गई।

छत्तीसगढ़ की जनता भी है त्रस्त, कह रही है अब ये है भूपेश का जिहादगढ़

रायपुर। भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी प्रशांत सिंह ठाकुर ने कहा कि बेमेतरा में सनातनी हिंदू भाई की हत्या की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसके 4 दिन बाद यह कांग्रेस सरकार जागने का ढोंग कर रही है, इस सरकार को उसकी वास्तविक स्थिति और आईना दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने रोष व्यक्त करते हुए ट्विटर पर नंबर 3 पर ट्रेंड किया भूपेश का जिहादगढ़... यह ट्रेंड बताता है कि छत्तीसगढ़ की अराजक स्थिति पर जनता का क्या मत है.. भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक सोमेशचंद्र पांडेय ने कहा कि जिहादियों के कारनामों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के संरक्षण पर छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा दिया गया तमाचा है, पूरे देश मे नं 3 पर ट्रेंड होना त्त भूपेश का जिहादगढ़ भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश सह संयोजक मितुल कोठारी ने कहा कि बेमेतरा जिले के बिरनपुर गाँव में जेहादियों द्वारा हिन्दू युवक भुवनेश्वर साहू की नृशंस हत्या पर पूरे देश की जनता ने ट्विटर पर त्तभूपेशट्ठकाट्ठजिहादगढ़ को नं 3 पर ट्रेंड कर जताया रोष बेमेतरा के साजा विधानसभा अंतर्गत बिरनपुर गांव में जिहादियों द्वारा हिंदू युवक भुनेश्वर साहू की नृशंस हत्या पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर प्रदेशव्यापी बंद सफल रहा जिसे भाजपा ने भी समर्थन प्रदान किया।

भाजपा के षडयंत्रों के कारण आरक्षण बिल को राजभवन में अटके 5 माह हो गये - कांग्रेस

रायपुर। आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन में अटके 5 माह पूरे होने को है। अभी तक राजभवन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा के आदिवासी नेता आरक्षण विधेयक पर अपना रुख साफ करें। आरक्षण संशोधन बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने का कारण भाजपा का अडंगा है यह प्रदेश की जनता भलिभांति समझ रही है। हम चुनाव में इसे भाजपा के खिलाफ मुद्दा बनायेंगे। आरक्षण संशोधन विधेयक में आदिवासी समाज के लिये 32 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। बिलासपुर हाई कोर्ट से 58 प्रतिशत आरक्षण को 50 प्रतिशत किये जाने पर आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आरक्षण विधेयक राजभवन में रुका है तो इसका खामियाजा आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा हो रहा। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है वह हस्तक्षेप कर आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने को कहे। राज्यपाल बदली हो गये किन आरक्षण बिल पर फैसला नहीं हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पारित करवाये गये आरक्षण संशोधन विधेयक में ओबीसी के लिये भी 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई - कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिरनपुर की घटना में मृत भुवनेश्वर साहू के परिजनों को दस लाख रू. का मुआवजा तथा उनके परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। सरकार ने दोषियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये है 11 आरोपी जेल के सीखचों के पीछे है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिये है जो भी और दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्यवाही होगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता शांति की बहाली में बाधक है। छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दो के दिवालियेपन से जूझ रही है। उसके पास जनहित के लिये उठाने को कुछ बचा नहीं है। इसीलिये भाजपा अब धर्म और सांप्रदायिकता का गंदा कार्ड खेलने के दुष्चक्र में लगी है। कवर्धा में भी ऐसा ही प्रयास हुआ, बिरनपुर की घटना के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और कमल भंजदेव लोगों को मुस्लिमों-ईसाइयों के बहिष्कार की शपथ दिलवाकर भाजपा की अवसरवादी मानसिकता को प्रदर्शित किये है। इसके पहले भी झूठे धर्मातरण के मुद्दे को लेकर प्रदेश में माहौल बनाने की अनेकों कोशिशे हुई लेकिन राज्य की जनता ने भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब भाजपा एक बार फिर धार्मिक विद्वेष भड़काने का गंदा खेल खेलने की कोशिश में है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के नेता भुलावे में है कि सांप्रदायिक और धार्मिक भावना भड़काकर वे राज्य के अपनी खोई राजनैतिक जमीन

बंद के दौरान तोडफ़ोड़ और चक्काजाम करने वाले 200 प्रदर्शन कारियों पर मामला दर्ज

रायपुर, 11 अप्रैल (आरएनएस)। बेमेतरा के बिरनपुर गांव में हुई हिंसा में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में सोमवार को छत्तीसगढ़ बंद के दौरान राजधानी रायपुर में उपद्रव और तोडफ़ोड़ करने वाले 200 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया हैं। पुलिस ने बजरंग दल, वीएचपी समेत भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनाधिकृत चक्काजाम करने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। गोलबाजार थाना पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता केदार गुप्ता, संजू नारायण सिंह, अमरजीत चावला, चंद्रशेखर वर्मा, घनश्याम चौधरी, प्रदीप वाधवानी, प्रफुल्ल विश्वकर्मा और अमित साहू समेत 200 बजरंग दल, वीएचपी समेत भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनाधिकृत चक्काजाम करने की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इसी प्रकार जय स्तंभ चौक पर लंबे समय तक चक्काजाम कर यातायात बाधित किया गया जिससे आम जनता को अत्यधिक परेशानी हुई जिस पर ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध थाना गोल बाजार में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वहीं टीकरापारा थाना की पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता राजेश वैष्णव, किशोर, अजय और लव अमित समेत अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफजान से मारने की धमकी समेत रास्ता रोककर तोडफ़ोड़ समेत बलवा की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि बंद के दौरान थाना टिकरापारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित बस स्टैंड में कुछ लोगों द्वारा बस में तोडफ़ोड़ किया जिस पर व्यक्तियों को चिन्हित उनके विरुद्ध थाना टिकरापारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

छत्तीसगढ़ की वैभवशाली संस्कृति की है विशिष्ट पहचान- मुख्यमंत्री

- **राज्य में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने राम वन गमन पर्यटन परिपथ तथा 'कृष्ण कुंज' के निर्माण सहित हो रहे अनेक कार्य**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इण्डोर स्टेडियम में अयोजित 108 पोथी श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में शामिल हुए और पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कथास्थल में व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य भाई श्री रमेशभाई ओझा जी को शाल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल इस दौरान दर्शकदीर्घा में बैठकर कथा का श्रवण भी किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि श्रीमद भागवत कथा से ज्ञान, भक्ति और कर्म की शिक्षा के साथ असीम आनंद की अनुभूति होती है, जो हमारे जीवन को संवारने में अहम् होता है। उन्होंने राजधानी में 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक श्री गुजराती समाज, रायपुर द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आयोजन के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर आगे कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों से समृद्ध है, जो इसके वैभवशाली संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 'आरंग' एक ऐसी जगह है, जहां भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराम दोनों ही पधारे थे। हमारी सरकार द्वारा राज्य के ऐसे सभी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इस कड़ी में राम वन गमन पर्यटन परिपथ का भी निर्माण किया जा रहा है। जिसमें भगवान राम के प्रति स्थानीय लोगों की भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजा जा रहा है। इसके तहत राज्य में हर उस जगह को चिन्हित किया गया है, जहां से वनवास के दौरान भगवान राम गुजरे थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान राज्य में विकसित हो रहे 'कृष्ण कुंज' के बारे में भी अवगत कराया। इसके तहत समस्त नगरीय निकायों को चिन्हाकित किया गया है। जिसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के वृक्षों का रोपण शहरों की हरियाली में वृद्धि और स्वच्छ वातावरण के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, महापौर श्री एजाज ढेबर, गुजराती समाज के लोग तथा श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.